

घटना घटना

सत्य के साथ... जनहित में बात...

www.ghatatighatana.com अम्बिकापुर, तृष 22, अंक - 149- बुधवार 01- अप्रैल 2026, पृष्ठ - 8 मूल्य 2 रुपये RNI Reg.No.- CHHHIN/2004/15050, उक पंजीयन. क्रं. 13/Surguja DN/ 2026-2028

पीएम मोदी ने साणंद में सेमीकंडक्टर प्लांट का उद्घाटन किया भारत को इस सेक्टर में ग्लोबल हब बनाने का कोरोना काल में संकल्प लिया : पीएम मोदी

अहमदाबाद, 31 मार्च 2026। पीएम मोदी ने गुजरात के साणंद में केयन्स सेमीकॉन के आउटसोर्सिंग सेमीकंडक्टर असेंबली प्लांट का उद्घाटन किया। इसके बाद वे प्लांट देखने पहुंचे और इंजीनियर्स से बातचीत की। पीएम ने कहा... आज सुबह डिवाइन वाले कार्यक्रम में था और अब डिजिटल के कार्यक्रम में हूँ। उन्होंने कहा... हमने कोरोना के समय ही तय कर लिया था कि भारत सेमीकंडक्टर सेक्टर का नया हब बनेगा। पीएम के उद्घाटन के साथ ही केयन्स सेमीकंडक्टर प्लांट में प्रोफेशनल प्रोडक्शन शुरू हो जाएगा। पहला प्लांट भी फरवरी 2026 में साणंद में ही शुरू हुआ था। पीएम वाव-थराड में 20 हजार करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट्स का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे। इससे पहले उन्होंने सुबह करीब 10 बजे गांधीनगर में सम्राट स्मॉल्ट म्यूजियम का उद्घाटन किया। पीएम ने म्यूजियम का दौरा करने के बाद राष्ट्रीय स्तर पूजा आचार्य पद्मसागर सूर्यशर्मा का आशीर्वाद लिया।

म्यूजियम में 2 हजार से ज्यादा दुर्लभ चीजें

पीएम मोदी ने गांधीनगर में सम्राट स्मॉल्ट म्यूजियम में राष्ट्रीय स्तर पूजा आचार्य पद्मसागर सूर्यशर्मा का आशीर्वाद भी लिया। इस म्यूजियम में सात अलग-अलग विंग हैं, जहां दुर्लभ जैन चट्टानों, पत्थर और धातु की मूर्तियां, प्राचीन पांडुलिपियां, सिक्के, चांदी के रथ और मिनिचर पेंटिंग प्रदर्शित की गई हैं। म्यूजियम में दो हजार से ज्यादा दुर्लभ चीजें रखी गई हैं, जो जैन धर्म के विकास और उसके सांस्कृतिक प्रभाव को दर्शाती हैं।



पीएम बोले... यहाँ बने गॉड्रिल अमेरिका भेजे जाएंगे...

मुझे पता चला है कि यहाँ वर्तमान में निर्मित उत्पादों का एक बड़ा बैच एक्सपोर्ट के लिए पहले ही बुक हो चुका है। साणंद में उत्पादित गॉड्रिल अमेरिकी कंपनियों को आपूर्ति किए जाएंगे, जिससे दुनिया भर के उद्योगों को बिजली आपूर्ति में मदद मिलेगी। 'मेक इन इंडिया, मेक फॉर द वर्ल्ड' पहल का प्रभाव विश्व के हर कोने में महसूस किया जाएगा। क्रिटिकल मिनेरल्स में आत्मनिर्भरता के लिए नेशनल क्रिटिकल मिनेरल्स मिशन भी शुरू किया गया है। इसके तहत क्रिटिकल मिनेरल्स की माइनिंग और प्रोडक्शन पर जोर दिया जा रहा है। मिनेरल्स की रिसाइटिंग के लिए भी 1500 करोड़ रुपए की रकम शुरू की गई है। इस साल के बजट में ओडिशा, आंध्र प्रदेश तमिलनाडु, केरलम जैसे कोस्टल राज्यों को मिलाकर रेयर अर्थ कोरिडोर के निर्माण की घोषणा की गई है। यह कोरिडोर एक इंटीग्रेटेड नेटवर्क होगा, जो माइनिंग रिफाइनिंग और मेन्यूफैक्चरिंग को सशक्त वेन तैयार करेगा। हमारा प्रयास है कि देश में मिनेरल्स का एक नेशनल रिजर्व हो।

चीजें रखी गई हैं, जो जैन धर्म के विकास और उसके सांस्कृतिक प्रभाव को दर्शाती हैं।

मोदी ने कहा... भारत इस दिशा में मिशन मोड पर काम कर रहा : 2021 में भारत ने इंडिया सेमिकंडक्टर मिशन शुरू किया था। यह मिशन सिर्फ एक इंडस्ट्रियल पॉलिसी नहीं, बल्कि भारत के आत्मविश्वास का एलान था। अच्छा होता कि यह काम आज से 30-40 साल पहले शुरू हो गया

होता। लेकिन, भारत अब इस दिशा में बहुत तेजी से बढ़ रहा है। भारत इस दिशा में एक मिशन मोड पर काम कर रहा है। इस दशक में भारत टेक्नोलॉजी से जुड़े जो इनिशिएटिव ले रहा है, जो आने वाले दशकों में भारत की लीडरशिप को सशक्त करेंगे। 21वीं सदी का भारत केवल बदलाव का साक्षी नहीं, बल्कि बदलाव का नेतृत्व करने के संकल्प के साथ आगे बढ़ रहा है।

पीएम बोले... भारतीय कंपनियों को ग्लोबल सेमीकंडक्टर लक्ष्य देना है हमारा उद्देश्य

मोदी ने कहा... मुझे इस बात की खुशी है कि भारत की कंपनी ने सेमीकंडक्टर विप बनाने में रुचि दिखाई और नतीजा सबके सामने है। हमारे भारत की अपनी कंपनी केयन्स अब ग्लोबल सेमीकंडक्टर सप्लायर वेन देने जा रही है। आज का यह दिन मेक इन इंडिया, मेक फॉर द वर्ल्ड को सही मायनों में चरितार्थ करता है। उद्योग जगत के अनुमानों के मुताबिक आज भारत में सेमीकंडक्टर बाजार का मूल्य 50 अरब डॉलर (करीब 4.5 लाख करोड़ रुपए) है। इस दशक के आखिरी तक इसके 100 अरब डॉलर (करीब 9 लाख करोड़ रुपए) तक पहुंचने का अनुमान है। यह बदतीरी सेमीकंडक्टर बाजार की अपार संभावनाओं को उजागर करती है।

मोदी बोले... भारत का सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम तेजी से विकसित हो रहा

28 फरवरी को माहकॉन के प्लांट में प्रोडक्शन की शुरुआत हुई और आज 31 मार्च को केयन्स टेक्नोलॉजी के सेमीकंडक्टर प्लांट का प्रोडक्शन शुरू हो रहा है। यह सिर्फ संयोग नहीं है- यह इस बात का प्रमाण है कि भारत का सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम किस गति से विकसित हो रहा है।

नालंदा के शीतला माता मंदिर में भगदड़, 9 श्रद्धालुओं की मौत

नालंदा, 31 मार्च 2026। बिहार में नालंदा जिले में मंगलवार सुबह शीतला माता मंदिर में भगदड़ मच गई। हदसे में 9 लोगों की मौत हो गई। 8 महिलाओं की भीड़ में दबने से मौके पर ही मौत हो गई थी, जबकि एक पुरुष ने अस्पताल में दम तोड़ा। चैत्र महीने के आखिरी मंगलवार को बड़ी संख्या में श्रद्धालु इस मंदिर में पहुंचे थे। वहां मेला भी लगा था। मौके पर मौजूद लोगों ने बताया कि भीड़ को संभालने के लिए पर्याप्त इंतजाम नहीं थे। दर्शन करने की जल्दी में धक्का-मुक्की मच गई। अफरातफरी के बीच कई लोग भीड़ में दब गए। बड़ी संख्या में लोग घायल भी हुए हैं। हदसे के बाद मंदिर और मेला को बंद करवा दिया है।



पहले 2-3 पुलिस वाले पहुंचे। उनके साथ मिलकर श्रद्धालुओं ने घायल महिलाओं को किनारे लिटाया। कई बार एंबुलेंस के लिए फोन किया गया। घटना के करीब 40 मिनट बाद पहली एंबुलेंस पहुंची और पुलिस के कुछ अफसर भी आए। इसके बाद घायलों को अस्पताल भिजवाया गया। महिलाओं को उठाते समय ही लग रहा था कि उनमें से कुछ की मौत हो गई है।

दर्शन की जल्दबाजी में गयी भगदड़

महिला भक्तों ने बताया कि चैत्र महीने का ये आखिरी मंगलवार है। यहां मेला लगा था। भीड़ ज्यादा हो गई। मंदिर का गर्भगृह भी छोटा है। लोग जल्दी-जल्दी दर्शन करने के लिए एक-दूसरे से आगे निकलने की कोशिश में थे। कोई लाइन में लगकर पूजा नहीं करना चाह रहा था। दूसरे श्रद्धालु ने बताया, 'सुरक्षा का कोई इंतजाम नहीं किया गया था। मंदिर के अंदर भारी भीड़ थी। पुलिस का जवान अंदर तेनात नहीं था। भीड़ को डायवर्ट करने या दो लाइनों में बांटने की कोई व्यवस्था नहीं थी। मंदिर के पुजारी ही जल्दी-जल्दी दर्शन कर निकलने को कह रहे थे। इस बीच एक महिला को चक्कर आ गया, जिससे वो वहीं गिर पड़ी। कुछ लोग उसे संभालने लगे, और भीड़ को पीछे करने की कोशिश की। इस दौरान भगदड़ मच गई।'

40 मिनट बाद पहुंची एंबुलेंस

मंदिर में मौजूद एक श्रद्धालु ने बताया, 'भगदड़ के बाद कई महिलाएं बेहोश पड़ी थीं। कुछ दर्द से चिल्ला रही थीं। लोगों ने पुलिस को खबर की।

मंदिर प्रबंधन ने व्यवस्था नहीं की

आज चैत्र का आखिरी मंगलवार है। मचड़ा शीतला मंदिर में इस दिन हर साल भीड़ होती है, मंदिर प्रबंधन को इस बात की जानकारी थी, इसके बाद भी भीड़ को व्यवस्थित रखने के लिए अलग से कोई इंतजाम नहीं किया गया था। भीड़ को कंट्रोल करने के लिए मंदिर परिसर में बैरिकेडिंग तक नहीं की गई थी। सुबह 8 से 9 बजे के बीच भीड़ अत्यधिक बढ़ गई।

घोर दरवाजे से दर्शन कराए जा रहे थे...

बढ़ती भीड़ को कंट्रोल करने की बजाए मंदिर प्रबंधन और वहां मौजूद पुजारी फायदा उठा रहे थे। वे लोगों से पैसा लेकर पीछे के दरवाजे से माता का दर्शन कराने लगे। इन्हें रोकने वाला कोई नहीं था, ये अपनी मरमांनी कर रहे थे। इसके कारण लोगों में नाराजगी बढ़ती चली गई।

सूरत के घर में लगी भीषण आग जिंदा जलकर 5 लोगों की मौत



गुजरात, 31 मार्च 2026। गुजरात के सूरत शहर में बड़ा हादसा हुआ है। यहां के लिंबावत इलाके में एक तीन मंजिला मकान में आग लगने से एक ही परिवार के पांच लोगों की मौत हो गई। मरने वालों में चार महिलाएं और एक छोटा बच्चा शामिल है। यह हादसा मंगलवार सुबह करीब 10 बजे मोठी खाड़ी इलाके में हुआ। पुलिस और दमकल विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर राहत और बचाव कार्य शुरू किया।

राष्ट्रीय पैकिंग के दौरान लगी आग

पुलिस के अनुसार, जिस मकान में आग लगी वहां साड़ी पैकिंग का काम होता था। हादसे के समय परिवार के सदस्य फोम शीट की मदद से साड़ियों को पैक कर रहे थे। छुट्टी का दिन होने के कारण घर में पैकिंग का काफी सारा सामान और फोम जमा था। इसी दौरान अचानक आग लग गई और देखते ही देखते पूरे कमरे में काला धुआं भर गया।

दम घुटने से गई पांच लोगों की जान

उप पुलिस आयुक्त कानन देसाई ने बताया कि आग लगने की सूचना मिलते ही पुलिस, फायर ब्रिगेड और 108 एंबुलेंस मौके पर पहुंची। कमरे के अंदर धुआं ही धुआं भरा था। लोग अंदर फंसे लोगों का दम घुटने लगा। गंभीर हालत में सभी को अस्पताल ले जाया गया, लेकिन इलाज के दौरान उन्होंने दम तोड़ दिया।

अवैध गतिविधि में धन का दुरुपयोग रोकने को लाया गया एफसीआर विधेयक : रिजिजू



नई दिल्ली, 31 मार्च 2026। केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री रिजिजू ने विदेशी अंशदान (विनियमन) संशोधन विधेयक-2026 को लेकर विपक्षी दलों के आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि किसी भी अवैध गतिविधियों में धन के दुरुपयोग को रोकने के लिए यह विधेयक लाया गया है। रिजिजू ने मंगलवार को भाजपा मुख्यालय में पत्रकारों से बातचीत के दौरान कहा कि केरल में वामदलों और कांग्रेस द्वारा कुछ अफवाहें फैलाई जा रही हैं कि भारत सरकार विभिन्न धार्मिक संगठनों की गतिविधियों को रोकने के लिए एफसीआर संशोधन विधेयक ला रही है, लेकिन प्रस्तावित संशोधन विधेयक केवल भारत में विदेशी धन के विनियमन के लिए, किसी भी अवैध गतिविधि में धन के दुरुपयोग को रोकने के लिए लाया गया है। उन्होंने कहा कि विदेशों से अवैध रूप से पैसा आता है और उसका इस्तेमाल राष्ट्रीय सुरक्षा के खिलाफ किया जाता है। इसलिए राष्ट्रीय सुरक्षा और राष्ट्रहित में प्रस्तावित संशोधन लेकर सरकार लाई है। रिजिजू ने आरोप लगाया कि वामपंथी दल और कांग्रेस प्रस्तावित संशोधन को लेकर झूठी अफवाहें फैला रहे हैं, क्योंकि वे केरल विधानसभा चुनावों से पहले भाजपा को मिल रहे भारी जनसमर्थन से भयभीत हैं। यह विधेयक किसी भी धार्मिक समूह के खिलाफ नहीं है। उन्हें इस तरह के झूठ फैलाना बंद कर देना चाहिए। उल्लेखनीय है कि विदेशी अंशदान (विनियमन) संशोधन विधेयक विगत 25 मार्च को लोकसभा में पेश किया गया था। पेश करते हुए केंद्रीय गृह राज्यमंत्री नित्यानंद राय ने कहा था कि इस विधेयक का उद्देश्य पारदर्शिता बढ़ाना और विदेशों से प्राप्त धन का उचित उपयोग सुनिश्चित करना है।

कैबिनेट मंजूरी के बाद पांच राज्यों को जल जीवन मिशन 2.0 के तहत 1,561 करोड़ रुपये जारी

नई दिल्ली, 31 मार्च 2026। केंद्र सरकार ने देश में ग्रामीण घरों तक सुरक्षित पेयजल पहुंचाने के लिए जल जीवन मिशन 2.0 के तहत पांच राज्यों को वित्त वर्ष 2025-26 के लिए फंड जारी कर दिए हैं। केंद्रीय कैबिनेट से 10 मार्च को मंजूरी मिलने के बाद यह राशि राज्यों को आवश्यक अनुपालन शर्तें पूरी करने पर दी गई है। केंद्रीय जलशक्ति मंत्रालय के अनुसार उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, ओडिशा और मध्य प्रदेश को कुल 1,561.53 करोड़ रुपये दिए गए हैं। इसमें उत्तर प्रदेश को 792.93 करोड़, छत्तीसगढ़ को 536.53 करोड़, मध्य प्रदेश को 154.02 करोड़, ओडिशा को 65.31 करोड़ और महाराष्ट्र को 12.74 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं।



कैबिनेट ने जल जीवन मिशन 2.0 के लिए कुल 8.69 लाख संरचनात्मक सुधार किए गए हैं। राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को फंड जारी करने से पहले कई अनिवार्य शर्तें पूरी करनी होती हैं। इनमें सुधार आधारित एमओयू पर हस्ताक्षर, योजनाओं का 'सुजलाम भारत' जोआईएस लिंकड एसेट

मायके से मिली संपत्ति पर पति का अधिकार नहीं, निःसंतान महिला का सबकुछ पिता के वारिस को मिलेगा : आंध्र हाईकोर्ट

अमरावती, 31 मार्च 2026। आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने कहा है कि किसी हिंदू महिला को माता-पिता से विवसत में संपत्ति मिली है और उसकी मौत बिना संतान, वसीयत किए बिना ही हो जाती है, तो उस संपत्ति पर पति-ससुराल का कानूनी हक नहीं होगा। ऐसी संपत्ति महिला के पिता के कानूनी वारिसों को जाएगी। जस्टिस तारलाड राजशेखर राव ने कहा कि हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 की धारा 15(2)(ए) इस बारे में साफ है। मामला एक परिवार की संपत्ति से जुड़ा है। 2002 में एक महिला ने अपनी संपत्ति पहली नातिन को गिफ्ट कर दी थी। 2005 में उस नातिन की बिना संतान मौत हो गई। इसके बाद नातिन ने पुराना गिफ्ट रद्द कर संपत्ति दूसरी नातिन के नाम वसीयत कर दी। 2012 में दादी की मौत के बाद दूसरी नातिन ने राजस्व रिपोर्ट में नाम दर्ज कराने का आवेदन किया। राजस्व अधिकारी ने दूसरी नातिन के पक्ष में आदेश दिया, लेकिन मृत नातिन के पति ने इसे चुनौती दी।

तिरुवनंतपुरम, 31 मार्च 2026। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने केरल विधानसभा चुनाव को लेकर अपना घोषणापत्र मंगलवार को जारी कर दिया। 'यही बदलाव है, यही विकसित केरल है' थीम पर आधारित इस घोषणापत्र में राज्य के समग्र विकास का रोडमैप पेश किया गया है, जिसमें बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स, सामाजिक कल्याण योजनाओं और प्रशासनिक सुधारों पर विशेष जोर दिया गया है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने तिरुवनंतपुरम स्थित श्री मूलम क्लब में आयोजित कार्यक्रम

डबल इंजन की सरकार असम को विकास और समृद्धि के नए युग की ओर आगे बढ़ रही : राजनाथ

असम, 31 मार्च 2026। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मंगलवार को कहा कि डबल इंजन की सरकार आज असम को विकास और समृद्धि के नए युग की ओर आगे बढ़ रही है। असम विधान सभा चुनाव के मद्देनजर शोणितपुर जिला के तेजपुर विधान सभा क्षेत्र में आयोजित एक जनसभा को संबोधित करते हुए केंद्रीय रक्षा मंत्री सिंह ने भाजपानीत सरकार की उपलब्धियों की जहां चर्चा की, वहीं विपक्ष की कांग्रेस की नीतियों की जमकर आलोचना की। उन्होंने कहा कि भाजपा का संकल्प है कि हर कीमत पर असम की संस्कृति और पहचान की रक्षा हो। असम के लोगों का सम्मान हो। यहां का विकास हो। इसी संकल्प के साथ आज डबल इंजन की सरकार असम को विकास और समृद्धि के नए युग की ओर आगे बढ़ रही है।

बाएं में बात होती थी तो उपावाद की बात होती थी। अशांति की बात होती थी। अस्थिरता की बात होती थी। असम और नॉर्थ-ईस्ट के विकास को नई दिशा और नई ऊर्जा देने का काम सबसे पहले अटल बिहारी वाजपेयी ने किया था। उन्होंने पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास के लिए एक समर्पित मंत्रालय बनाया था। ताकि असम और पूरे पूर्वोत्तर के विकास को विशेष प्राथमिकता दी जा सके। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरे पूर्वोत्तर के विकास को सबसे ज्यादा प्राथमिकता दी है। राजनाथ सिंह ने कहा कि आज जब पूर्वोत्तर की बात होती है तो विकास की बात होती है। कनेक्टिविटी की बात होती है। 'अष्टशक्ती' की बात होती है। यहाँ के संभावना की बात होती है। प्रगति की बात होती है। समृद्धि की बात होती है। आज, असम नए

केरल चुनाव के लिए भाजपा का घोषणा पत्र जारी...साल में दो गैस सिलेंडर मुफ्त, बुजुर्गों को 3 हजार पेंशन का वादा



के दौरान यह घोषणा पत्र जारी किया। इस मौके पर पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष राजीव चंद्रशेखर, टीवी-20 पार्टी के मुख्य समन्वयक साबू जैकब, वीडियोएस के प्रदेश अध्यक्ष तुषार वेल्लात्तिल और तिरुवनंत

अखिल भारतीय आधुनिकीकरण संस्थान (एम्स) की स्थापना का है, जो राज्य की लंबे समय से चली आ रही मांग रही है। परिवहन क्षेत्र में पार्टी ने तिरुवनंतपुरम से कन्नूर तक हाई-स्पीड रेल कॉरिडोर बनाने का वादा किया है, जिससे राज्य में यात्रा का समय काफी कम होने की उम्मीद है। इसके साथ ही शहरी भीड़भाड़ को कम करने के लिए तिरुवनंतपुरम और कोझिकोड में मेट्रो रेल परियोजनाएं शुरू करने की योजना भी पेश की गई है।

आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ रहा है। यह विकास का केंद्र बन रहा है। असम पूरे पूर्वोत्तर के विकास का इंजन बनकर उभर रहा है। जब असम आगे बढ़ेगा, तो पूरे भारत के विकास को रफ्तार मिलेगी। जब असम विकसित होगा तब ही भारत विकसित होगा। उन्होंने कहा कि पिछले दस सालों में भाजपा के शासन में असम की अर्थव्यवस्था लगभग तीन गुना बढ़ गई है। मुख्यमंत्री हिमंत बिस्म सरमा के कार्यकाल में असम देश की सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था बनकर सामने उभरा है। आज जब सरकार की सही नीति और नियति के साथ असम के लोगों की मेहनत और ऊर्जा मिली है तो असम ने विकास की रफ्तार पकड़ी है। यहां उद्योग बढ़ रहे हैं। निवेश बढ़ रहा है। और तेजी से इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास हुआ है। उन्होंने कहा कि असम ने

2030 तक अपनी अर्थव्यवस्था को लगभग डेढ़ सौ बिलियन डॉलर तक पहुंचाने का लक्ष्य निर्धारित किया है। मुझे पूरा विश्वास है कि असम इस लक्ष्य को जरूर हासिल करेगा। चिकित्सा हो या शिक्षा, आधारभूत संरचना हो या उद्योग, आज असम हर क्षेत्र में अभूतपूर्व वृद्धि कर रहा है। यहां नए एम्स और आईआईएम जैसे कोशिकाओं में मेट्रो रेल परियोजनाएं शुरू करने की योजना भी पेश की गई है।

संपादकीय



पहचान के संकट से जूझते समुदाय

हम प्रायः समाज को कोटियों यानी वर्गों या श्रेणियों में बांटकर देखने के आदी हो गए हैं। दलित, जनजाति, सवर्ण, हिंदू, मुस्लिम जैसी अनेक कोटियां समाज को देखने के हमारे नजरिये पर हावी रहती हैं...

हम प्रायः समाज को कोटियों यानी वर्गों या श्रेणियों में बांटकर देखने के आदी हो गए हैं। दलित, जनजाति, सवर्ण, हिंदू, मुस्लिम जैसी अनेक कोटियां समाज को देखने के हमारे नजरिये पर हावी रहती हैं। हम अक्सर समाज को इन्हीं स्थिर वर्गों के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं और मान लेते हैं कि सामाजिक वास्तविकता इन्हीं सीमाओं के भीतर पूरी तरह समाहित हो जाती है, लेकिन हम यह नहीं सोचते कि इन कोटियों के बीच भी अनेक ऐसे सामाजिक समूह मौजूद हो सकते हैं, जो इन निर्धारित श्रेणियों में पूरी तरह समाहित नहीं होते। हम यह भी समझना नहीं चाहते कि ये कोटियां हमेशा कठोर और स्थायी नहीं होतीं, बल्कि कई बार लचीली और परिवर्तनशील भी होती हैं। सामाजिक जीवन की जटिलता कई बार इन कोटियों की सीमाओं को चुनौती देती है।

वास्तव में समाज की संरचना इतनी सरल नहीं होती कि उसे केवल कुछ तयशुदा श्रेणियों में पूरी तरह समझ लिया जाए। दलित एवं जनजाति दो ऐसी कोटियां हैं, जिन्हें हमारी राजनीति और प्रशासनिक व्यवस्था ने विशेष रूप से निर्मित किया है। औपनिवेशिक जनगणना के दौरान पहली बार अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की कोटियां बनाकर अनेक विविध सामाजिक समूहों को उनमें सम्मिलित कर दिया गया। औपनिवेशिक शासन की रणनीति समाज को अलग-अलग वर्गों में बांटकर शासन को सरल बनाना और कई बार विभाजन की रेखाएँ खींचना भी था। इसके परिणामस्वरूप कई ऐसे समुदाय बने रहे, जो इन श्रेणियों में रखे जाने के बावजूद अपनी सांस्कृतिक पहचान को अलग ढंग से समझते एवं विश्लेषित करते रहे।

उदाहरण के लिए, कई दलित जातियां दलित कोटि में दर्ज होने के बावजूद अपने आपको जनजातीय विशेषताओं से युक्त मानती रही हैं। उत्तर प्रदेश और बिहार में रहने वाले मुसहर समुदाय को प्रशासनिक रूप से दलित कोटि में दर्ज किया गया है, किंतु अपनी सामाजिक और सांस्कृतिक आत्मसंज्ञा में वे अपने आपको कई जनजातीय विशेषताओं से युक्त मानते हैं। इसी प्रकार उत्तर प्रदेश के कई क्षेत्रों में कोल और खखार जैसे समुदायों को प्रशासनिक दृष्टि से अनुसूचित जाति में रखा गया है, जिन्हें कई स्थानों पर जनजातीय माना जाता है। उनके दैनिक जीवन, कर्मकांड, पूजा-पद्धति और सांस्कृतिक व्यवहार में वे से जनजातीय संस्कृति की स्पष्ट छाप दिखाई देती है। यह स्थिति दर्शाती है कि सामाजिक वास्तविकता प्रशासनिक वर्गीकरण से कहीं अधिक जटिल और बहुआयामी होती है।

इन दोनों कोटियों के बीच भी कई ऐसे सामाजिक समूह मौजूद हैं, जो न पूरी तरह इधर के हैं और न पूरी तरह उधर के। वे सामाजिक संरचना में एक प्रकार की मध्यवर्ती स्थिति में रहते हैं। ऐसे समूहों को सिद्धांतकार 'बीच के समूह', 'बीच की अस्थिरता वाले समुदाय' अथवा 'लिमिनल आइडेंटिटी' वाले समूह कहते हैं। ये समुदाय समाज की मुख्यधारा में होते हुए भी कई बार पहचान और अधिकार के स्तर पर अस्पष्ट स्थिति में रहते हैं। उत्तर प्रदेश में ऐसा ही एक समूह है-वनदांगिया समुदाय, जो मुख्यतः महाराजगंज एवं गोरखपुर क्षेत्र के जंगलों में बसता है। इनका मुख्य कार्य जंगलों में विशेष पद्धति से साखू के पेड़ लगाना था। यह स्पष्ट नहीं है कि ये समुदाय कब और कैसे इस क्षेत्र में आए, परंतु इतना निश्चित है कि अंग्रेजी शासन के समय से ही ये इस कार्य से जुड़े रहे हैं।

लंबे समय तक यह समुदाय प्रशासनिक और सामाजिक दृष्टि से उपेक्षित रहा है। लंबे समय तक उनकी जमीनी भी उनकी अपनी नहीं थी। जिन बस्तियों में वे रहते थे, उन्हें वैध मान्यता प्राप्त नहीं थी। उन्हें मतदान का अधिकार भी प्राप्त नहीं था और न ही सरकारी योजनाओं का लाभ व्यवस्थित रूप से मिल पाता था। जब किसी समुदाय की पहचान और निवास का वैध आधार ही न हो, तब विकास की योजनाएं भी उन तक पहुंच नहीं पातीं।

निजीकरण का बोलबाला: सरकारी स्कूलों पर गहराता संकट

एक दशक में 94 हजार सरकारी स्कूल बंद, प्राइवेट 51 हजार खुले, स्कूल जाने योग्य हर पांचवां बच्चा स्कूल से बाहर...



सत्यवान सोराय
भिवानी हरियाणा

भारत की शिक्षा व्यवस्था आज एक गंभीर संकट के दौर से गुजर रही है। पिछले एक दशक में लगभग 94 हजार सरकारी स्कूल बंद हो चुके हैं, जबकि इसी अवधि में 51 हजार से अधिक निजी स्कूल खुल गए हैं। यह स्थिति न केवल सरकारी शिक्षा प्रणाली की कमजोरियों को उजागर करती है, बल्कि बढ़ते निजीकरण के कारण उत्पन्न सामाजिक असमानता को भी सामने लाती है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत प्रत्येक बच्चे को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार दिया गया है, लेकिन वर्तमान परिस्थितियों में यह अधिकार धीरे-धीरे कमजोर पड़ता दिखाई दे रहा है। 2014-15 से 2023-24 के बीच सरकारी स्कूलों की संख्या 11,07,101 से घटकर 10,17,660 रह गई, यानी लगभग 89,441 स्कूल कम हो गए, जबकि निजी स्कूलों की संख्या 2,88,164 से बढ़कर 3,31,108 हो गई। यह प्रवृत्ति विशेष रूप से ग्रामीण भारत के लिए चिंताजनक है, जहां गरीब और वंचित वर्गों के बच्चों के लिए शिक्षा तक पहुंच लगातार कठिन होती जा रही है।

सरकारी स्कूलों के संकट का एक प्रमुख कारण स्कूल मंजूर नीति है, जिसके तहत कम नामांकन वाले छोटे स्कूलों को बड़े स्कूलों में मिला दिया जाता है। इससे ग्रामीण और आदिवासी क्षेत्रों में बच्चों के लिए स्कूल तक पहुंच कठिन हो गई है। मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में हजारों स्कूल बंद हुए हैं, जो कुल बंदी का बड़ा हिस्सा है। इसके अलावा, शिक्षकों की कमी, कमजोर आधारभूत संरचना और मिड-डे मील जैसी योजनाओं का सही ढंग से क्रियान्वयन न होना भी नामांकन में गिरावट के प्रमुख कारण हैं। National Education Policy 2020 के कुछ प्रावधान, जैसे एकल शिक्षक स्कूलों को हतोत्साहित करना, भी इस प्रक्रिया को प्रभावित करते हैं, जिसके परिणामस्वरूप सरकारी स्कूलों में नामांकन में भारी कमी आई है, जबकि निजी स्कूलों में छात्रों की संख्या तेजी से बढ़ी है। गरीब परिवारों के बच्चे अब मजबूरन निजी स्कूलों की ओर रुख कर रहे हैं, लेकिन ऊंची फीस उनके लिए एक बड़ी बाधा बन जाती है। निजी स्कूलों की संख्या में तेजी से वृद्धि हो रही है और शहरी क्षेत्रों में बड़ी संख्या में बच्चे निजी स्कूलों में पढ़ रहे हैं। हालांकि यह वृद्धि कई चिंताएं भी पैदा करती है। निजी स्कूलों में फीस में भारी वृद्धि देखी जा रही है, जिससे निम्न और मध्यम आय वर्ग के परिवारों के लिए शिक्षा प्राप्त करना कठिन होता जा रहा है। शिक्षा का यह बढ़ता निजीकरण उसे एक सामाजिक सेवा से अधिक एक व्यापार में बदलता जा रहा है। शिक्षा का अधिकार कानून के तहत 25 प्रतिशत सीटें गरीब बच्चों के लिए आरक्षित हैं, लेकिन इसका प्रभावी क्रियान्वयन नहीं हो पा रहा है, जिससे सामाजिक असमानता और गहरी हो रही है। एक ओर संपन्न वर्ग बेहतर संसाधनों और सुविधाओं वाले निजी स्कूलों में शिक्षा प्राप्त करता है, वहीं दूसरी ओर गरीब वर्ग सीमित



संसाधनों वाले सरकारी स्कूलों तक ही सीमित रह जाता है। इस असंतुलन का सीधा प्रभाव ड्रॉपआउट दर पर भी पड़ रहा है। पिछले कुछ वर्षों में लाखों बच्चों ने स्कूल छोड़ दिया है, जिनमें बड़ी संख्या किशोरियों की है। इसके पीछे गरीबी, बाल श्रम, परिवार का प्रवास, स्कूलों की दूरी और सुरक्षा की कमी जैसे कई कारण जिम्मेदार हैं। विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में लड़कियों के लिए शिक्षा प्राप्त करना अधिक कठिन हो जाता है। जब परिवार निजी स्कूलों की फीस वहन नहीं कर पाते और आसपास सरकारी स्कूल उपलब्ध नहीं होते, तो बच्चों का शिक्षा से बाहर होना लगभग तय हो जाता है। यह स्थिति आने वाले समय में बेरोजगारी और सामाजिक असमानता को और अधिक बढ़ा सकती है। शिक्षा का निजीकरण केवल एक शैक्षिक समस्या नहीं है, बल्कि यह सामाजिक और आर्थिक असमानता को भी गहराता है। जब सभी वर्गों को समान शिक्षा के अवसर नहीं मिलते,

तो समाज में अवसरों का असंतुलन बढ़ता जाता है। भारत में शिक्षा पर सकल घरेलू उत्पाद का केवल लगभग 3 प्रतिशत ही खर्च किया जाता है, जबकि इसे 6 प्रतिशत तक बढ़ाने का लक्ष्य अभी भी अधूरा है। इसका प्रभाव महिलाओं के सर्वाधिकरण, रोजगार के अवसरों और देश के समग्र आर्थिक विकास पर पड़ता है। यदि यह स्थिति बनी रही, तो यह लोकतंत्र के लिए भी खतरा बन सकती है, क्योंकि एक शिक्षित समाज ही जागरूक और जिम्मेदार नागरिक तैयार करता है। इस संकट से निपटने के लिए सरकार को ठोस और प्रभावी कदम उठाने होंगे। स्कूल मंजूर नीति पर पुनर्विचार किया जाना चाहिए और ग्रामीण क्षेत्रों में छोटे स्कूलों को संरक्षित किया जाना चाहिए। रिक्त शिक्षक पदों को शीघ्र भरा जाए और शिक्षकों के प्रशिक्षण पर विशेष ध्यान दिया जाए। सभी स्कूलों में बुनियादी सुविधाएं जैसे शौचालय, स्वच्छ पेयजल और डिजिटल संसाधन सुनिश्चित किए जाएं। मिड-डे

मील योजना की गुणवत्ता में सुधार किया जाए और निजी स्कूलों की फीस पर नियंत्रण तथा गिरावट बढ़ाई जाए। शिक्षा का अधिकार कानून के प्रावधानों को सख्ती से लागू किया जाए और शिक्षा पर सार्वजनिक निवेश बढ़ाकर इसे सकल घरेलू उत्पाद के 6 प्रतिशत तक पहुंचाया जाए। निजीकरण का बढ़ता प्रभाव सरकारी स्कूलों के लिए एक गंभीर चुनौती बन चुका है। सरकारी स्कूलों की घटती संख्या और निजी स्कूलों की बढ़ती संख्या यह संकेत देती है कि शिक्षा धीरे-धीरे एक मौलिक अधिकार से हटकर एक व्यापार का रूप लेती जा रही है। इसका सबसे अधिक प्रभाव गरीब और वंचित वर्गों पर पड़ रहा है। यदि समय रहते उचित कदम नहीं उठाए गए, तो यह असमानता समाज को गहराई तक प्रभावित करेगी। शिक्षा को बाजार की वस्तु नहीं, बल्कि सामाजिक विकास का आधार मानते हुए इसे मजबूत करना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि स्वच्छ पीढ़ियों का भविष्य इसी पर निर्भर करता है।

मूर्ख दिवस आज पर विशेष

मूर्ख दिवस : हमारा मजाक न बने किसी की पीड़ा का कारण



योगेश कुमार गोयल
नजफगढ़, नई दिल्ली



तनाव भरे दौर में मुस्कान का पर्व है मूर्ख दिवस

विश्वभर में 1 अप्रैल को मनाया जाने वाला 'मूर्ख दिवस' केवल एक साधारण दिन नहीं बल्कि हंसी, उलझन और हल्के-फुल्के मजाक का ऐसा अवसर है, जो लोगों को रोजमर्रा की तनावपूर्ण जिंदगी से कुछ पल के लिए राहत प्रदान करता है। इस दिन छोटे-बड़े, बच्चे-बुजुर्ग, सभी

एक-दूसरे के साथ मजाक करते हैं और बिना किसी दुर्भावना के हंसी-ठिठोली के माध्यम से माहौल को खुशनुमा बना देते हैं। इस दिवस की सबसे खास बात यह है कि इसमें किए जाने वाले मजाक आमतौर पर हानिरहित होते हैं। लोग ऐसी कल्पनात्मक या मनगढ़ंत बातें प्रस्तुत करते हैं, जो सामने वाला आसानी से विश्वास कर ले और बाद में जब सच्चाई सामने आए तो दोनों पक्ष हंसी में डूब जाएं। कई बार तो बड़े-बड़े बुद्धिमान और चतुर लोग भी इस दिन मजाक का शिकार बन जाते हैं, जिससे वातावरण और भी मनोरंजक हो उठता है। यह परंपरा केवल आम लोगों तक सीमित नहीं रही है बल्कि बड़े मीडिया संस्थान, प्रतिष्ठित कंपनियों और नामी ब्रांड भी इस दिन अनोखे और रचनात्मक 'प्रैक्स' के जरिए लोगों का मनोरंजन करते हैं। इतिहास में कई रोचक उदाहरण मिलते हैं। 1957 में बोबीसी ने 'स्मेटोटी ट्री' की खबर प्रसारित की, जिसमें बताया गया कि रिवट्रजरलैंड में पेड़ों पर स्मेटोटी उगती है। हजारों लोगों ने इस पर विश्वास कर लिया। इसी तरह 1996 में बर्गर किंग ने 'लेप्ट-हैड डॉगर' बर्गर की

घोषणा कर लोगों को चौंका दिया। डिजिटल युग में यह परंपरा और भी व्यापक हो गई है। सोशल मीडिया और ऑनलाइन प्लेटफॉर्मों के जरिए ऐसे मजाक कुछ ही मिनटों में लाखों लोगों तक पहुंच जाते हैं। हालांकि, कभी-कभी लोग सच्ची खबरों को भी 'अप्रैल फूल' समझकर नजरअंदाज कर देते हैं और बाद में पछाते हैं। मूर्ख दिवस की उत्पत्ति को लेकर विभिन्न मत हैं। एक प्रचलित धारणा के अनुसार, प्राचीन समय में कई देशों में नया वर्ष 1 अप्रैल से शुरू होता था। जब कैलेंडर प्रणाली में बदलाव हुआ और नए साल की शुरुआत 1 जनवरी से होने लगी, तब भी कुछ लोग पुरानी परंपरा का पालन करते रहे। ऐसे लोगों का मजाक उठाने के लिए 1 अप्रैल को 'मूर्ख दिवस' के रूप में मनाया जाने लगा। धीरे-धीरे यह परंपरा मनोरंजन का माध्यम बन गई। भारतीय संस्कृति में भले ही यह परंपरा प्राचीन समय से आई हो लेकिन इसके मूल में निहित भावना (हंसी, आनंद और आपसी मेलजोल) भारतीय जीवन की भांगी और तनावपूर्ण जीवनशैली में

जहां लोगों के पास हंसने का समय भी कम हो गया है, वहां यह दिन एक सुखद अवसर प्रदान करता है। हालांकि, यह ध्यान रखना आवश्यक है कि मजाक की सीमा शालीनता और संवेदनशीलता के भीतर ही होनी चाहिए। किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाने, अपमान करने या नुकसान पहुंचाने वाला मजाक इस दिवस की भावना के विपरीत है। मूर्ख दिवस का उद्देश्य किसी को नीचा दिखाना नहीं बल्कि सबको साथ लेकर हंसना और खुशियां बांटना है। वास्तव में, शुद्ध हास्य न केवल मानसिक तनाव को कम करता है बल्कि आपसी संबंधों को भी मजबूत बनाता है। यह मन में सकारात्मकता और भाईचारे की भावना का संचार करता है। ऐसे में मूर्ख दिवस आज के समय में और भी अधिक प्रासंगिक हो जाता है। अंततः कहा जा सकता है कि मूर्ख दिवस केवल मजाक का दिन नहीं बल्कि जीवन में खुशियों के छोटे-छोटे पल तलाशने और उन्हें साक्षात् करने का उत्सव है। यदि इसे शालीनता और सद्भाव के साथ मनाया जाए तो यह दिन सचमुच हंसी के अनमोल पलों से जीवन को सराबोर कर सकता है।

स्वतंत्रता संग्राम सेनानी क्रांतिकारी परसराम सोनी की कहानी

लक्ष्मीनारायण लहरे साहिल, रायपुर, छत्तीसगढ़

1942 में अपने साथियों के साथ मिलकर सरकार के विरुद्ध बगावत की योजना बना रहे थे, जिससे अंग्रेजों में खलबली मच जाए यह घटना पूरे छत्तीसगढ़ में क्रांति की एक चिंगनी लहर लेकर आती, अंग्रेज परसराम जी को पकड़ने के लिए पूरी ताकत लगा चुके थे। लेकिन परसराम जी की गिरफ्तारी एक दोस्त की गद्दारी के कारण हुई। 15 जुलाई, 1942 को जब वे गोलबाजार परभूलाल पतिराम बाड़े से गिरालाल मिस्त्री से रिवांछण और कारतूस लेकर साइकिल से लौट रहे थे तो उनके साथ उनका एक गद्दार मित्र एडवर्ड रोड जहां सदर रोड से मिलती है उसी तिमाह में, इस मित्र ने पहले से पुलिस को सूचना दे दी थी। सदर के पास पहुंचते ही उसने साइकिल की घंटी बजा कर पुलिस को संकेत दिया था। पुलिस ने परसराम को रिवांछण सहित गिरफ्तार कर लिया। उसके बाद गिरफ्तारी और तलाशी का सिलसिला चल पड़ा सुधीर मुखर्जी, गिरिलाल मिस्त्री, विपिन बिहारी सूर, निखिल भूपुर सूर, कृष्णा एवं धिरे, रणवीर सिंह शास्त्री, भूपेन्द्र नाथ मुखर्जी, दशरथ चौबे, कुंजबिहारी चौबे, क्रांतिकुमार, हेरोलाल सोनी आदि लोगों की गिरफ्तारियां हुईं। उस समय परसराम जी की उम्र केवल 22 साल के थे। मुकदमे शुरू हुई पूरा बार रूम के वकीलों की हमदर्दी क्रांतिकारियों के साथ थी सरकार को पैरवी करने के लिए वकील नहीं मिल रहे थे, क्रांतिकारियों के तरफ से श्री पी भादुरी, श्री एम भादुरी श्री एहमद अली, श्री चौदाकर, श्री पेन्डाकर, श्री इशराद अली व चुक्रीलाल जी अग्रवाल आदि वकीलों ने पैरवी की। परसराम जी को 7 साल की सजा सुनाई गई, गिरिलाल जी को 8 साल की सजा सुनाई गई, लेकिन जेल में भी उनका हासला नहीं टूटा। वे लगातार अपने साथियों को संघर्ष जारी रखने के लिए प्रेरित करते रहे। 1946 में, 4 साल जेल में रहने के बाद, उन्हें एवं गिरिलाल जी को रिहा कर दिया गया, इससे पहले सभी लोग पहले रिहा हो चुके थे।



परसराम सोनी

डांस, दिल और दिमाग का लोकतंत्र

सुभाष बुझाने वाला, रतलाम, मध्य प्रदेश

वैसे तो यह परंपरा सदियों से चली आ रही है कि महिलाएं अपने पतियों को उंगली पर नचाती हैं, लेकिन अब विज्ञान ने भी इस पर मुहर लगा दी है, बस थोड़ा सभ्य तरीके से। पहले जहां सास-बहू के सीरियल्स और मोहल्ले की चाची लोग इस विषय पर शोध किया करती थीं, वहीं अब यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिक भी इस नाच-गान में कूद पड़े हैं। फर्क बस इतना है कि चाची लोग निकरफे पहले निकाल लेती थीं, और वैज्ञानिक बाद में। ब्रिटेन के शोधकर्ताओं ने बड़े ही गंभीर चेहरे और महंगे फंड के सहारे यह पता लगाया कि पुरुष अगर डांस करते समय अपनी कमर के ऊपरी हिस्से को हिलाएं तो महिलाएं आकर्षित होती हैं, और महिलाएं अगर अपने पैरों का इस्तेमाल ज्यादा करें तो पुरुषों का दिल फिसल जाता है। अब यह शोध सुनकर हमारे मोहल्ले के शर्मा जी बहुत दुखी हैं। वे पिछले 25 साल से शादीशुदा हैं और उन्होंने कभी डांस किया ही नहीं, क्योंकि उनकी पत्नी ने साफ मना कर रखा है कि तुम नाचोगे तो मैं मायके चली जाऊंगी। शोधकर्ताओं ने यह भी बताया कि हाथों का ज्यादा महत्व नहीं है। अब यह बात सुनकर उन लोगों को बड़ा धक्का लगा है जो शादी-ब्याह में सिर्फ हाथ उठाकर नागिन डांस करते हैं। उन्हें अब समझ आ गया है कि वे अब तक बेकार में ही अपनी कलाई तोड़ते रहे। असली खेल तो कमर और पैरों

का था, जो वे कभी समझ ही नहीं पाए। डॉक्टर निक नीव ने तो यहां तक कह दिया कि पुरुष डांस महिलाओं को आकर्षित करने के लिए नहीं, बल्कि दूसरे पुरुषों को अपनी ताकत दिखाने के लिए करते हैं। यानी डांस फ्लोर अब युद्धभूमि बन चुका है। फर्क बस इतना है कि यहां तलवार की जगह कमर लचकती है और ढाल की जगह स्टाइलिश जैकेट होती है। अब अगर किसी शादी में आप किसी अंकल को जोश में आकर डांस करते देखें, तो समझ जाइए कि वे किसी आंटी को नहीं, बल्कि सामने वाले गुप्ता जी को चुनौती दे रहे हैं, देखो भाई, अभी भी दम है!

महिलाओं के मामले में भी कहानी कम दिलचस्प नहीं है। वे डांस को एक संकेत की तरह लेती हैं। अब यह संकेत क्या होता है, यह समझना अब आदमी के बस की बात नहीं। जैसे रेलवे स्टेशन पर खड़े होकर आप यह नहीं समझ पाते कि ट्रेन लैट है या प्लेटफॉर्म ही गलत है, वैसे ही पुरुष यह नहीं समझ पाते कि महिला का डांस 3-गिन सिग्नल है या रेड अलर्ट। शोध में यह भी सामने आया कि पुरुषों को कमर लचकाने वाली महिलाएं ज्यादा पसंद आती हैं। अब यह बात सुनकर जिम जाने वाले लड़कों को थोड़ी राहत मिली है। वे अब तक सिक्स पैक एक्स बनाने में लगे थे, लेकिन अब उन्हें समझ आ गया है कि असली खेल तो लचक का

है। अब जिम में डबल कम और डांस क्लास ज्यादा दिखेंगे। लेकिन इस पूरे शोध में एक बात बड़ी दिलचस्प है! यह सब बातें हम भारतीयों को पहले ही पता थीं। हमारे यहां तो बचपन से ही कहा जाता है, नाच न जाने आंगन टेढ़ा। यानी अगर आपको डांस नहीं आता, तो आप आकर्षण के इस खेल में पहले ही बाहर हो चुके हैं। हमारे यहां शादियों में जो डांस होता है, वह किसी भी यूनिवर्सिटी के शोध से कहीं ज्यादा एडवांस होता है। वहां अंकल लोग कमर के ऊपरी हिस्से का इस्तेमाल करते हैं, आंटी लोग पैरों का, और बच्चे पूरे शरीर का। और सबसे खास बात! वहां कोई जजमेंट नहीं होता। जो जैसा नाच सकता है, वैसे नाचता है। कोई नागिन बन जाता है, कोई घोड़ा, और कोई तो ऐसा नाचता है कि खुद उसे भी समझ नहीं आता कि वह क्या कर रहा है। वैज्ञानिकों का यह शोध सुनकर ऐसा लगता है कि अब भविष्य में शादी से पहले डांस टेस्ट लिया जाएगा। जैसे पहले लड़के से पूछा जाता था, कितनी सैलरी है? अब पूछा जाएगा, कमर कितनी लचकती है? और लड़कियों से पूछा जाएगा, पैरों का मूवमेंट कैसा है? अगर दोनों पास हो गए, तो रिश्ता पक्का। लेकिन असली सवाल यह है कि क्या डांस ही आकर्षण का पैमाना है? अगर ऐसा है, तो

हमारे देश के आधे से ज्यादा लोग तो सिंगल ही रह जाएंगे, क्योंकि उन्हें डांस से ज्यादा प्यार सोने से है। और जो डांस करते भी हैं, वे सिर्फ इसलिए कि शादी में खाना देर से मिल रहा है। सच तो यह है कि यह पूरा शोध थोड़ा दिल बहलाने वाला है। इसका का आकर्षण सिर्फ डांस से तय नहीं होता। अगर ऐसा होता, तो हर डांसर सबसे ज्यादा खुश होता और हर इंजीनियर अकेला। लेकिन हकीकत इससे कहीं ज्यादा जटिल है। फिर भी, इस शोध का एक फायदा जरूर है! अब लोगों को डांस करने का नया बहाना मिल गया है। पहले लोग कहते थे, मुझे डांस नहीं आता। अब कहेंगे, मैं रिसर्च के लिए डांस कर रहा हूँ। और अंत में, मैं यही कहूंगा कि चाहे आप कमर हिलाएं, पैर चलाएं या सिर्फ खड़े होकर ताली बजाएं, डांस का असली मजा तब है जब आप उसे दिल से करें। क्योंकि आकर्षण का सबसे बड़ा फॉर्मूला कोई वैज्ञानिक नहीं, बल्कि आपका आत्मविश्वास तय करता है। बाकी जहां तक पतियों को उंगली पर नचाने की बात है, उस पर तो अभी तक कोई शोध नहीं हुआ। लेकिन अनुभव के आधार पर कहा जा सकता है कि इसमें महिलाओं की पीएचडी पहले से ही पूरी है, और पुरुष अभी भी इंटरनिशप कर रहे हैं।

सूचना
समाचार पत्र में छपे समाचार एवं लेखों पर सम्पादक की सहमति आवश्यक नहीं है। हमारा ध्येय तथ्यों के आधार पर सफिक खबरें प्रकाशित करना है न कि किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना। सभी विवादों का निपटारा अम्बिकापुर न्यायालय के अधीन होगा।

सम्पादक

युवक की हत्या करने वाला आरोपी गिरफ्तार

-संवाददाता-
अंबिकापुर, 31 मार्च 2026
(घटती-घटना)।



लुण्डा थाना क्षेत्र के ग्राम करेसर में 29 मार्च को टांगी से मार कर युवक की मौत के घाट उतारने के मामले में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ कार्रवाई कर जेल दाखिल कर दिया है। जानकारी के अनुसार राकेश पिता स्व. बनारसी उम्र 20 वर्ष ग्राम पटोरा जोबलापारा थाना लुण्डा का रहने वाला था। राकेश 29 मार्च को दोस्त रामसाय व संजय के साथ बाइक से ग्राम करेसर गया था। संजय को उसके घर छोड़ने के बाद ग्राम पटोरा का रहने वाला बुधसाय उर्फ धूर साय मिला, जिसे बाइक में बैठकर बस्ती की तरह ले जा रहा था। बाइक राम साय चला रहा था। राम साय के आंख में कौड़ी घूस गया। जो हैडपंप के पास बाइक को रोक कर चेहरा धोया, हैडपंप बुधसाय चला रहा था। इसके बाद राकेश पानी पीने के लिए फिर से बुधसाय को हैडपंप चलाने के लिए बोला। इस बात पर बुधसाय नाराज हो गया और गाली देने लगा। इस दौरान राकेश ने उसे धक्का दे दिया। गुस्से में हथ में रखे टांगी से बुधसाय ने राकेश पर हमला कर दिया। जिसे इलाज के दौरान मेडिकल कॉलेज अस्पताल में मौत हो गई। घटना की जानकारी मिलने पर थाना लुण्डा पुलिस मौके पर पहुंचकर मामले की जांच की। वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी भाग गया था। घटना के तीसरे दिन आरोपी बुधसाय उर्फ जीबाल को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से घटना में प्रयुक्त टांगी भी जब्त किया है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ कार्रवाई कर जेल दाखिल कर दिया है।

स्कूटी सवार ठेकेदार से मारपीट मोबाइल फोन पटका

-संवाददाता-
अंबिकापुर, 31 मार्च 2026 (घटती-घटना)।

स्कूटी अड्डकर एक अन्य स्कूटी में सवार ठेकेदार के साथ गाली-गलौज, मारपीट और मोबाइल फोन पटक कर क्षतिग्रस्त कर देने का मामला सामने आया है। पुलिस ने आरोपी के विरुद्ध अपराध दर्ज कर लिया है। घटना अजिमा स्थित कृषि महाविद्यालय के पास की है। ठेकेदारी करने वाले सुभाषनगर,बाबरा बगीचा निवासी संजय जायसवाल ने रिपोर्ट दर्ज कराया है कि 17 मार्च की रात को करीब 8.30 बजे वह अपने घर से साथी सिकन्दर के साथ पटवारी पारस जाटव का स्कूटी वाहन छोड़ने भावानपुर रोड होते हुए पटवारीया जा रहा था। इसी बीच अजिमा कृषि कॉलेज के पास उनकी स्कूटी के सामने हॉपित चक्रवर्ती अपने स्कूटी क्रमक सीजी 15 ईजी 1259 को अचानक रोक दिया,जिससे मार्ग अवरुद्ध हो गया। इस दौरान विवाद की स्थिति बनी और हॉपित चक्रवर्ती मुक्का से नाक व मुंह में वार करके जान से मारकर गाड़ देने की धमकी देने लगा। आरोपित की हकत का जब ठेकेदार संजय ने वीडियो बनाने का प्रयास किया, तो वह मोबाइल को पटक दिया। मारपीट के दौरान ठेकेदार ने पर्स भी गायब होने का आरोप लगाया है। मारपीट में आई चोटों का इलाज कराने के बाद ठेकेदार ने घटना की रिपोर्ट गांधीनगर थाना में दर्ज कराई है, जिस पर पुलिस ने बीएनएस की धारा 115(2), 126(2),296,324(4),351(3) का मामला दर्ज कराया है।

सड़क हादसे में युवक की मौत

-संवाददाता-
अंबिकापुर, 31 मार्च 2026 (घटती-घटना)।

जगरनाथपुर स्कूल के पास 30 मार्च को बाइक सवार युवक अनियंत्रित होकर वैरिक्ट से टकराकर सड़क पर गिर गया और गंभीर रूप से घायल हो गया था। जिसकी मौत मेडिकल कॉलेज अस्पताल में हो गई थी। वहीं परिजन को घटना की जानकारी दूसरे दिन लगी। तो अस्पताल पहुंचे। जानकारी के अनुसार रामलाल पिता मान साय उम्र 25 वर्ष राजपुर थाना क्षेत्र के गाम चौरा का रहने वाला था। 10-15 दिन से वह ससुराल जगरनाथपुर में रह रहा था। 30 मार्च को वह बाइक से काम करने खड़ाया जा रहा था। तभी जगरनाथपुर मिशन स्कूल के पास वैरिक्ट से टकराकर सड़क पर गिरकर घायल हो गया था। पुलिस उसे एंबुलेंस से इलाज के लिए मेडिकल कॉलेज अस्पताल भिजवा दी थी।

संजय पार्क से फिर हिरण फरार... वन विभाग की लापरवाही पर उठा सवाल

-संवाददाता-
अंबिकापुर, 31 मार्च 2026
(घटती-घटना)।

वन विभाग की लापरवाही थमने का नाम नहीं ले रही है। कुछ दिन पहले ही संजय पार्क में आवारा श्वानों के हमले में 15 हिरणों की मौत का मामला सामने आया था, और अब सोमवार रात एक और घटना ने विभाग की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े कर दिए हैं। जानकारी के अनुसार, सोमवार को पार्क का कर्मचारी हिरणों को चारा देने के लिए बाड़े में गया था। इसी दौरान बाड़े का गेट खुला रह गया और एक हिरण मौके का फायदा उठाकर जंगल की ओर भाग निकला। घटना की जानकारी मिलते ही वन विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों में हड़कंप मच गया। देर रात तक टीम जंगल में टॉच लेकर हिरण की तलाश करती रही, लेकिन उसका कोई पता नहीं चल सका। अधिकारियों को आशंका है कि जंगल में भटक रहे हिरण पर आवारा श्वानों का खतरा बना हुआ है। गौरतलब है कि एक सप्ताह पहले ही संजय पार्क में आवारा श्वानों ने बाड़े में घुसकर हिरणों पर हमला कर दिया था, जिसमें 15 हिरणों की मौत हो गई थी। इस घटना की उच्च स्तरीय जांच अभी तक पूरी नहीं हो पाई है। लगातार हो रही घटनाओं के बावजूद वन विभाग के जिम्मेदार अधिकारी इस मामले में कुछ भी कहने से बच रहे हैं। ताजा घटना के बाद पार्क की सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। फिलहाल एहतियात के तौर पर संजय पार्क को आम लोगों के लिए बंद कर दिया गया है।



आम आदमी पार्टी नेता राजेन्द्र बहादुर सिंह के गंभीर आरोप...प्रदर्शन की चेतावनी

संजय पार्क से एक बार फिर हिरण के गायब होने की खबर ने वन विभाग की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े कर दिए हैं। इस मामले को लेकर आम आदमी पार्टी के नेता राजेन्द्र बहादुर सिंह ने वन विभाग पर गंभीर आरोप लगाए हैं और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है।

खबर चला सब अधिभक्त: जानकारी के अनुसार, हिरण के गायब होने की सूचना के बाद वन विभाग की टीम रातभर जंगल में उसकी तलाश करती रही। हालांकि अब तक हिरण का कोई पता नहीं चल पाया है।

वन विभाग पर लापरवाही के आरोप: आम आदमी पार्टी नेता राजेन्द्र बहादुर सिंह ने आरोप लगाया कि यह घटना वन विभाग की घोर लापरवाही का नतीजा है। उन्होंने कहा कि विभाग जंगल संरक्षण के बजाय अरब कटाई पर आंखें मूंदे हुए है। उनका दावा है कि बांसावाड़ी क्षेत्र में खुलेआम जंगल काटे जा रहे हैं, लेकिन विभागीय अधिकारी कोई कार्रवाई नहीं कर रहे।



हिरणों की मौत पर भी उच्च स्तर पर जांच: उन्होंने पूर्व में हुई लगभग 15 हिरणों की मौत को लेकर भी गंभीर आरोप लगाए। उनका कहना है कि हिरणों को चारा बचाने के उद्देश्य से जंगल में छोड़ा जाता था, जहां पर्याप्त सुरक्षा नहीं थी। इसी दौरान कुत्तों के झुंड ने उन पर हमला किया। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि वन विभाग द्वारा इस मामले में श्रमक जानकारी दी गई।

अधिकृत अनियमितताओं का आरोप: आम आदमी पार्टी नेता ने यह भी आरोप लगाया कि विभागीय अधिकारी

पशुओं के चारे और देखावत के नाम पर फर्जी बिल बनाकर सरकारी धन का दुरुपयोग कर रहे हैं। हालांकि इन आरोपों को स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है।

प्रदर्शन की चेतावनी

मामले को लेकर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं में आक्रोश है। राजेन्द्र बहादुर सिंह ने कहा कि पार्टी विरोध प्रदर्शन करेगी और दोषियों को जेल भेजने की मांग करेगी। साथ ही उन्होंने वन मंत्री से नैतिकता के आधार पर इस्तीफा देने की मांग भी की।

विभाग का पक्ष

वन विभाग की ओर से मामले की जांच की बात कही जा रही है। अधिकारियों का कहना है कि गायब हुए हिरण की तलाश जारी है और पूरे घटनाक्रम की जांच के बाद ही स्थिति स्पष्ट हो सकेगी।

अंबिकापुर सकालो में अफ्रीकन स्वाइन फीवर वैक्सिन का पहला ट्रायल प्रारम्भ...



-संवाददाता-
अंबिकापुर, 31 मार्च 2026 (घटती-घटना)।

अफ्रीकन स्वाइन फीवर (एएसएफ) जैसी अत्यंत घातक एवं संक्रामक वायरल बीमारी की रोकथाम के लिए अंबिकापुर के सकालो स्थित शासकीय पिंग फार्म में एएसएफ वैक्सिन का ट्रायल प्रारंभ किया गया है। यह ट्रायल नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ हार्ड सिक्नेरिटी एनिमल डिजीज (भोपाल) द्वारा विकसित वैक्सिन पर किया जा रहा है। यह परीक्षण पशुपालन विभाग के निर्देशानुसार वैज्ञानिक पद्धति से संचालित किया जा रहा है। इस वैक्सिन के विकास एवं परीक्षण में वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉ. वेक्टर एवं डॉ. संधिल कुमार की प्रमुख भूमिका है। वरिष्ठ पशु चिकित्सक,पिंग फार्म अंबिकापुर डॉ. सीके मिश्रा ने बताया कि विभागीय मार्गदर्शन में ट्रायल का संचालन किया जा रहा है, जिससे भविष्य में इस घातक बीमारी की प्रभावी रोकथाम हेतु ठोस समाधान प्राप्त होने की संभावना है। अफ्रीकन स्वाइन फीवर सूअरों में होने वाली एक अत्यंत जानलेवा बीमारी है, जिसकी मृत्यु दर बहुत अधिक होती है। यह बीमारी घरेलू एवं जंगली दोनों प्रकार के सूअरों को प्रभावित करती है। वर्तमान में इस रोग का कोई प्रभावी उपचार उपलब्ध नहीं है तथा संक्रमित पशुओं के नियंत्रण हेतु क्यूलिंग, क्वारंटाइन एवं आवासन नियंत्रण जैसे उपाय अपनाए जाते हैं। उल्लेखनीय है कि देश में एएसएफ वैक्सिन का यह प्रथम ट्रायल है। वर्तमान में भारत ही नहीं, बल्कि विश्व स्तर पर भी एएसएफ का कोई पूर्ण रूप से स्वीकृत (कमर्शियल) वैक्सिन उपलब्ध नहीं है। ऐसे में अंबिकापुर में प्रारंभ हुआ यह ट्रायल सूअर पालन क्षेत्र के लिए एक महत्वपूर्ण पहल एवं आशा की किरण के रूप में देखा जा रहा है।

मोबाइल बनवाने निकला युवक फांसी लगाकर किया खुदकुशी

-संवाददाता-
अंबिकापुर, 31 मार्च 2026
(घटती-घटना)।

मोबाइल बनवाने के लिए घर से निकला युवक फांसी लगाकर खुदकुशी कर लिया। मामले में पुलिस ने मार्ग कायम कर लिया है। जानकारी के मुताबिक कोतवाली थाना क्षेत्र के खैरबाबा गाड़ाघाट निवासी उतम टोपों पिता रामप्रसाद टोपों 20 वर्ष, 28 मार्च की शाम को करीब सात बजे अपने घर में मोबाइल बनवाने के लिए जा रहा हूंकहकर निकला था,इसके बाद घर वापस नहीं लौटा। मोबाइल खराब रहने के कारण उससे स्वजन का संपर्क भी नहीं हो पा रहा था। स्वजन उसकी खोजबीन में लगे थे। इसी बीच 29 मार्च की सुबह पड़ोसी की नजर पेड़ में लटक एक व्यक्ति पर पड़ी और उन्होंने इसकी जानकारी युवक के स्वजन को दी। इसकी सूचना मिलने पर स्वजन मौके पर पहुंचे, तो उतम का शव फांसी पर लटक रहा था। इसकी सूचना पुलिस को दी गई, मौके पर पहुंची कोतवाली थाना पुलिस ने शव को फांसी के फंदे से उतरवाया और मौका पंचनामा किया। स्वजन ने मोबाइल नहीं बनने से श्रद्धा होकर फांसी जैसा कदम उठाने की संभावना व्यक्त की है।



मोबाइल बनवाने के लिए घर से निकला युवक फांसी लगाकर खुदकुशी कर लिया। मामले में पुलिस ने मार्ग कायम कर लिया है। जानकारी के मुताबिक कोतवाली थाना क्षेत्र के खैरबाबा गाड़ाघाट निवासी उतम टोपों पिता रामप्रसाद टोपों 20 वर्ष, 28 मार्च की शाम को करीब सात बजे अपने घर में मोबाइल बनवाने के लिए जा रहा हूंकहकर निकला था,इसके बाद घर वापस नहीं लौटा। मोबाइल खराब रहने के कारण उससे स्वजन का संपर्क भी नहीं हो पा रहा था। स्वजन उसकी खोजबीन में लगे थे। इसी बीच 29 मार्च की सुबह पड़ोसी की नजर पेड़ में लटक एक व्यक्ति पर पड़ी और उन्होंने इसकी जानकारी युवक के स्वजन को दी। इसकी सूचना मिलने पर स्वजन मौके पर पहुंचे, तो उतम का शव फांसी पर लटक रहा था। इसकी सूचना पुलिस को दी गई, मौके पर पहुंची कोतवाली थाना पुलिस ने शव को फांसी के फंदे से उतरवाया और मौका पंचनामा किया। स्वजन ने मोबाइल नहीं बनने से श्रद्धा होकर फांसी जैसा कदम उठाने की संभावना व्यक्त की है।

पीजी कॉलेज अंबिकापुर में फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम सम्पन्न



-संवाददाता-
अंबिकापुर, 31 मार्च 2026
(घटती-घटना)।

राजीव गांधी शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय में 23 से 30 मार्च तक 'टीचिंग लर्निंग मेथड' विषय पर सात दिवसीय फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य शिक्षकों को आधुनिक शिक्षण पद्धतियों से परिचित कराना और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप शिक्षण को अधिक प्रभावी बनाना रहा। कार्यक्रम के संयोजक प्रो. राजकमल मिश्र ने बताया कि इस दौरान कुल 10 सत्र आयोजित किए गए, जिनमें देश के विभिन्न हिस्सों से आए विशेषज्ञों ने व्याख्यान दिए। इन सत्रों में लर्निंग

आउटकम, प्रॉब्लम सॉल्विंग तकनीक, क्रिटिकल व एनालिटिकल लॉगिंग, प्रश्नपत्र निर्माण, संज्ञानात्मक शिक्षण, शिक्षण-भाषा, सहभागिता आधारित शिक्षण तथा आईसीटी और एआई के उपयोग जैसे विषयों पर विस्तार से चर्चा हुई। कार्यक्रम के उद्घाटन अवसर पर मुख्य अतिथि सरगुजा संभाग के क्षेत्रीय अपर संचालक प्रो. रिजवान उल्ला ने कहा कि इस प्रकार के आयोजन शिक्षकों को नई दिशा देते हैं और अन्य महाविद्यालयों को भी प्रेरित करते हैं। मुख्य वक्ता प्रो. पीपी सिंह (पूर्व कुलपति) ने शिक्षण में नवाचार और शोध को बढ़ावा देने की आवश्यकता पर बल दिया। प्राचार्य प्रो. अनिल कुमार सिन्हा ने अध्यक्षीय उद्घोषण में कहा कि महाविद्यालय इस तरह के प्रशिक्षण



कार्यक्रमों के माध्यम से शिक्षण में सुधार के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि विद्यार्थियों को केवल किताबी ज्ञान ही नहीं, बल्कि जीवन की समझ भी देना जरूरी है, जिसके लिए शिक्षकों का प्रशिक्षित होना आवश्यक है। समापन सत्र में मुख्य अतिथि के रूप में प्रो. आरएन सिंह (पूर्व प्राचार्य, दुर्ग) उपस्थित रहे। उन्होंने कहा कि शिक्षक का व्यवहार और उसकी शिक्षण शैली विद्यार्थियों के जीवन में बड़ा परिवर्तन ला सकती है। इसलिए शिक्षकों को अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए समाज और राष्ट्र निर्माण में सक्रिय भूमिका निभानी चाहिए। कार्यक्रम में महाविद्यालय सहित संभाग के विभिन्न कॉलेजों के शिक्षकों की सक्रिय भागीदारी रही।

राष्ट्रपति के 'दत्तक पुत्र' पहाड़ी कोरवा दूषित पानी पीने को मजबूर नल-जल और पीएम जनमन योजना के दावों की खुली पोल



-विशेष संवाददाता-
बलरामपुर, 31 मार्च 2026
(घटती-घटना)।

एक ओर सरकार नल-जल योजना और पीएम जनमन योजना के माध्यम से विशेष पिछड़ी जनजातियों के विकास के बड़े-बड़े दावे कर रही है, वहीं जमीनी हकीकत इन दावों की पोल खोलती नजर आ रही है। बलरामपुर जिले के कुसमी जनपद अंतर्गत ग्राम पंचायत सबाग के वार्ड क्रमांक 10 (झालबासा) से सामने आई तस्वीरें बेहद चिंताजनक हैं।

यहाँ निवासरत करीब 14 से 15 परिवार, जो पहाड़ी कोरवा जनजाति से हैं-जिनमें 'राष्ट्रपति के दत्तक पुत्र' के रूप में जाना जाता है-भीषण जल संकट से जूझ रहे हैं।



-विशेष संवाददाता-
बलरामपुर, 31 मार्च 2026
(घटती-घटना)।

हैं। हालात इतने खराब हैं कि ग्रामीणों को खुद से खोदी गई 'बोंदी' (कच्चा गड्ढा) का सड़ा-गला और दूषित पानी कपड़े से छानकर पीना पड़ रहा है।

वीरान जगह से लाना पड़ रहा पानी : ग्रामीण जिस स्थान से पानी ला रहे हैं, वह शमशान जैसी वीरान जगह है, जहाँ न तो कुआँ है, न तालाब और न ही कोई बोरवेल। हाथ से बनाए गए छोटे से गड्ढे (चूआँ) में जमा गंदा पानी ही उनकी प्यास बुझाने का एकमात्र सहाय है।

दो साल से अधूरी नल-जल योजना : इस मामले में जब पंचायत सचिव से चर्चा की गई, तो उन्होंने बताया कि नल-जल योजना का कार्य पिछले दो वर्षों से जारी है,

लेकिन अभी तक अधूरा है। साथ ही, पीएम जनमन योजना के तहत सड़क स्वीकृत होने के बावजूद निर्माण पूरा नहीं हुआ है, जिससे बोरिंग मशीन झालबासा पार तक नहीं पहुँच पा रही है।

अब बड़ा सवाल यह है कि—

- आखिर कब तक सड़क निर्माण पूरा होगा?
- नल-जल योजना कब तक धरातल पर आएगी?
- और कब इन आदिवासी परिवारों को स्वच्छ पेयजल मिल पाएगा?

बीमारी फैलने का खतरा : जिस पानी का उपयोग ग्रामीण कर रहे हैं, उसमें पेड़ों की पत्तियाँ सड़ रही हैं और गंदगी साफ दिखाई

देती है। ऐसे दूषित पानी के सेवन से बस्ती में गंभीर बीमारियों और महामारी फैलने का खतरा बढ़ गया है।

प्रशासन पर उठे सवाल : विशेष पिछड़ी जनजाति के रूप में चिन्हित और 'राष्ट्रपति के दत्तक पुत्र' कहे जाने वाले इन पहाड़ी कोरवा परिवारों की यह स्थिति प्रशासनिक लापरवाही को उजागर करती है। यह मामला जिला प्रशासन की कार्यप्रणाली पर गंभीर प्रश्नचिह्न खड़ा करता है। अब देखना यह होगा कि इस खबर के प्रकाशन के बाद प्रशासन कितनी तेजी से संज्ञान लेता है और क्या इन प्यासे आदिवासी परिवारों को उनका बुनियादी अधिकार-स्वच्छ पेयजल-मिल पाता है या नहीं।

रघुनाथपुर में पंडित दीनदयाल उपाध्याय शिक्षण महाविद्यालय प्रशिक्षण वर्ग आयोजित विधायक प्रबोध मिंज ने पार्टी सिद्धांतों और 'राष्ट्र प्रथम' के मंत्र पर दिया जोर



-संवाददाता-
अंबिकापुर, 31 मार्च 2026
(घटती-घटना)।

ग्राम पंचायत रघुनाथपुर के ऑडिटोरियम भवन में मंगलवार को पंडित दीनदयाल उपाध्याय शिक्षण महाविद्यालय 2026 के अंतर्गत लुण्डा मंडल का प्रशिक्षण वर्ग आयोजित किया गया। कार्यक्रम में लुण्डा विधायक प्रबोध मिंज मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए।

कार्यक्रम की शुरुआत ध्वजारोहण के साथ हुई। इसके बाद पंडित दीनदयाल उपाध्याय के छायाचित्र पर पूजा-अर्चना कर दीप प्रज्वलन एवं माल्यार्पण किया गया। इस दौरान पार्टी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने विधायक का पुष्पचूष भेंट कर स्वागत किया। विधायक प्रबोध मिंज ने अपने संबोधन में पार्टी के सिद्धांतों और

'पंच निष्ठा' पर चलते हुए संगठन को मजबूत करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि 'राष्ट्र प्रथम, पार्टी द्वितीय और व्यक्ति तृतीय' के सिद्धांत को अपनाकर ही संगठन को सशक्त बनाया जा सकता है। साथ ही कार्यकर्ताओं से निष्ठा और लगन के साथ प्रशिक्षण ग्रहण करने की अपील की।

बड़ी संख्या में कार्यकर्ता रहे उपस्थित : कार्यक्रम में जिला पंचायत अध्यक्ष निरुपा सिंह, उपाध्यक्ष देवनारायण यादव, जिला महामंत्री वैभव सिंह देव, मंडल अध्यक्ष सतीश जायसवाल, संजय गुप्ता, जयंत मिंज, विधायक प्रतिनिधि दीक्षा अग्रवाल सहित कई पदाधिकारी मौजूद रहे। इसके अलावा महिला मोर्चा संयोजिका धनीराम यादव, उपाध्यक्ष उपाध्याय, दिलीप प्रजापति सहित विभिन्न मोर्चों के नवनिर्वाचित पदाधिकारी और बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता शामिल हुए।

भाजपा अनुसूचित जाति मोर्चा की बैठक सम्पन्न, अंबेडकर जयंती की तैयारियों पर हुई चर्चा

-संवाददाता-
अंबिकापुर, 31 मार्च 2026
(घटती-घटना)।

संकल्प भवन स्थित भाजपा कार्यालय में अनुसूचित जाति मोर्चा की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक में आगामी 14 अप्रैल को मनाई जाने वाली डॉ. भीमराव अंबेडकर जयंती के अवसर पर विभिन्न कार्यक्रमों की रूपरेखा तैयार की गई। बैठक के दौरान वक्ताओं ने बाबा साहब के विचारों को जन-जन तक पहुंचाने और समाज में समरसता व जागरूकता बढ़ाने पर जोर

दिया। जयंती के अवसर पर विभिन्न सामाजिक, सांस्कृतिक एवं जनजागरूकता कार्यक्रम आयोजित करने का निर्णय लिया गया। इस बैठक में भाजपा के वरिष्ठ पदाधिकारी एवं मोर्चा के कार्यकर्ता बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। प्रमुख रूप से भाजपा महामंत्री विनोद हर्ष, महामंत्री अरुणा सिंह, जनमेजय मिश्रा, रविकान्त उराव, अनुसूचित जाति मोर्चा के महामंत्री आर.डी. चौहान, बबली महिमा टोपों, गौतम रवि सहित सभी पदाधिकारीगण शामिल हुए।



-संवाददाता-
अंबिकापुर, 31 मार्च 2026
(घटती-घटना)।

जनप्रतिनिधियों पर खर्च को लेकर उठा मुद्दा समाजसेवी सुजान बिंद का बयान...

-संवाददाता-
अंबिकापुर, 31 मार्च 2026
(घटती-घटना)।

देश में जनप्रतिनिधियों पर होने वाले खर्च को लेकर एक बार फिर बहस तेज हो गई है। समाजसेवी सुजान बिंद ने इस विषय पर बयान देते हुए कहा कि सांसदों और जनप्रतिनिधियों के वेतन-भत्तों की समीक्षा करने और चुनावी खर्च पर नियंत्रण लगाने की मांग की।

आंकड़ों को लेकर स्पष्टता जरूरी : इस बीच जानकारों का कहना है कि इस प्रकार के आंकड़े अक्सर सोशल मीडिया पर बिना आधिकारिक पुष्टि के प्रसारित होते हैं। सांसदों और विधायकों के वेतन एवं सुविधाएं अलग-अलग नियमों के तहत निर्धारित होती हैं, इसलिए वास्तविक खर्च का आकलन आधिकारिक स्रोतों के आधार पर ही किया जाना चाहिए।

जवाबदेही जरूरी है। सुजान बिंद ने यह भी कहा कि यदि इन खर्चों की समग्र समीक्षा की जाए, तो यह आंकड़ा और अधिक बढ़ सकता है। उन्होंने जनप्रतिनिधियों के वेतन-भत्तों की समीक्षा करने और चुनावी खर्च पर नियंत्रण लगाने की मांग की।

आंकड़ों को लेकर स्पष्टता जरूरी : इस बीच जानकारों का कहना है कि इस प्रकार के आंकड़े अक्सर सोशल मीडिया पर बिना आधिकारिक पुष्टि के प्रसारित होते हैं। सांसदों और विधायकों के वेतन एवं सुविधाएं अलग-अलग नियमों के तहत निर्धारित होती हैं, इसलिए वास्तविक खर्च का आकलन आधिकारिक स्रोतों के आधार पर ही किया जाना चाहिए।

सरकारी दावों की पोल खोलता ढाबतुमाड़ी: आजादी के दशकों बाद भी ग्रामीण 'ढोढ़ी' का पानी पीने को मजबूर

मूल भूत सुविधाओं के तसते ग्रामीण,सड़क बिजली साफ पानी और बेहतर स्वस्थ सुविधाओं का अभाव



राजन फाउंडेशन

कोरिया/एमसीबी, 31 मार्च 2026
(घटती-घटना)।

विकास के बड़े-बड़े दावों और करोड़ों के बजट के बीच वनांचल क्षेत्र का ग्राम ढाबतुमाड़ी आज भी अपनी बदहाली पर आंसू बहा रहा है, मूलभूत सुविधाओं से कोसों दूर इस गांव में न तो चलने को सुरक्षित सड़कें हैं और न ही पीने को स्वच्छ पानी। आलम यह है कि ग्रामीण आज भी आदिम युग की तरह झरिया और ढोढ़ी के भरसे अपनी प्यास बुझा रहे हैं।

जल जीवन मिशन: पाइप खड़े हैं,पर प्यासी है जनता

केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी 'जल जीवन मिशन' योजना ढाबतुमाड़ी में पूरी तरह फेल नजर आ रही है, गांव के स्कूल के पास एक



विशाल पानी टंकी खड़ी तो कर दी गई है,लेकिन विडंबना देखिए कि उसी स्कूल के बच्चों को पानी नसीब नहीं हो रहा है, गांव की गलियों में नल के ठीके तो खड़े कर दिए गए हैं, लेकिन उनमें

पानी की एक बूंद तक नहीं टपकती,स्थिति यह है कि ग्रामीण आज भी दूर-दराज के झरिया और ढोढ़ी से गंदा पानी लाने को विवश हैं,जिससे बीमारियों का खतरा मंडरा रहा है।

जर्जर सड़कें दे रही हैं हदसों को च्योता

गांव तक पहुंचने वाली मुख्य सड़क का अस्तित्व लगभग समाप्त हो चुका है, पूरी सड़क गड्ढों में तब्दील हो गई है, जिससे आवागमन किसी बड़ी चुनौती से कम नहीं है,जर्जर सड़क के कारण आए दिन लोग दुर्घटनाओं का शिकार हो रहे हैं,ग्रामीणों का कहना है कि रात के समय या आपात स्थिति में किसी मरीज को अस्पताल ले जाना हो,तो यह सड़क यमराज के मार्ग जैसी प्रतीत होती है।

शिक्षा और स्वास्थ्य व्यवस्था भी विलेटेटर पर...

गांव के भविष्य यानी स्कूली बच्चों के साथ भी खिलवाड़ हो रहा है, स्कूल का भवन अत्यंत जर्जर हो चुका है, जहाँ बैठना किसी खतरे से खाली नहीं है, वहीं स्वास्थ्य सुविधाओं की बात करें तो यहाँ की स्थिति भी 'बेहाल' है, ग्रामीणों को छोटी-छोटी बीमारियों के लिए भी शहर की दौड़ लगानी पड़ती है।

तस्वीरों में विकास, धरातल पर सन्नाटा: जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों की उदासीनता- ग्राम ढाबतुमाड़ी को इस बदहाली के पीछे सबसे बड़ा कारण प्रशासन और

क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों की गहरी उदासीनता है, चुनाव के समय वोट मांगने और बड़े बड़े वादे करने के बाद नेता आज ग्रामीणों का हाल जानने तक नहीं पहुंचते, आलम यह है कि गाँव की

जर्जर सड़कों और सूखे नलों की शिकायतें फाइलों में दबी दम तोड़ रही हैं,लेकिन किसी भी जिम्मेदार अधिकारी ने अब तक धरातल पर उतरकर वस्तुस्थिति का जायजा लेने की जहमत नहीं उठाई,जनप्रतिनिधियों के 'विकास' के दावे यहाँ के पथरों और गड्ढों में गुम हो चुके हैं, ग्रामीणों का आरोप है कि वे खुद को उगा हुआ महसूस कर रहे हैं, क्योंकि न तो शासन की योजनाओं का लाभ उन तक पहुंच रहा है और न ही कोई सुध लेने वाला है,यह उदासीनता स्पष्ट करती है कि ढाबतुमाड़ी जैसे सुदूर अंचल आज भी सिस्टम की प्राथमिकता सूची से कोसों दूर है।
आक्रोशित ग्रामीणों की चेतावनी- ग्रामीणों ने कहा कि कई बार प्रशासन को अवगत कराया,लेकिन केवल आश्वासन मिला। अगर जल्द ही सड़क, बिजली और पानी की व्यवस्था दुरुस्त नहीं हुई,तो हम उग्र आंदोलन के लिए बाध्य होंगे।

खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स 2026...सरगुजा में कुश्ती स्पर्धा का शानदार समापन

खिलाड़ियों ने अपनी कुशल तकनीक एवं रणनीति का प्रदर्शन कर पदक किए अपने नाम

पुरुष वर्ग में हिमाचल प्रदेश एवं महिला वर्ग में असम राज्य रहे ओवरऑल चैंपियन

-संवाददाता-
अम्बिकापुर,31 मार्च 2026
(घटती-घटना)।

छत्तीसगढ़ में आयोजित खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स 2026 अंतर्गत आज सरगुजा जिला मुख्यालय अम्बिकापुर के गांधी स्टेडियम में पिछले चार दिनों से जारी कुश्ती स्पर्धा का शानदार समापन आज हुआ। पूरे आयोजन के दौरान विभिन्न राज्यों से आए खिलाड़ियों के बीच जबरदस्त प्रतिस्पर्धा देखने को मिली। खिलाड़ियों ने अपनी कुशल तकनीक एवं रणनीति का प्रदर्शन कर पदक अपने नाम किए। समापन अवसर पर टीम चैंपियनशिप परिणाम घोषित किए। पुरुष वर्ग में हिमाचल प्रदेश ओवर ऑल चैंपियन रहा, वहीं जम्मू कश्मीर फर्स्ट रनरअप, महाराष्ट्र एवं झारखण्ड सेकंड रनरअप बना। महिला वर्ग में असम राज्य ओवर ऑल चैंपियन रहा, वहीं



झारखण्ड फर्स्ट रनरअप,कर्नाटक एवं तेलंगाना सेकंड रनरअप रहे।

ये रहे आज के पदक विजेता- आज आयोजित स्पर्धा में महिला सीनियर 57 किलोग्राम भारवर्ग में तेलंगाना की नागलक्ष्मी ने गोलड,कर्नाटक की शालीना सिद्धि ने सिल्वर,कर्नाटक की अमृत्या भीमसेन

कुन्दरी ने कांस्य पदक जीता। महिला सीनियर 68 किलोग्राम भारवर्ग में कर्नाटक के प्रिसिता पेडु फ्रानोन्डिस सिद्धि को गोलड, मिजोरम के एलजाबेथ रोहलुपुल्ल को सिल्वर,गुजरात के चावड़ा लीलाबन मैयाभाई एवं राजस्थान की बालकेश कुमारी मीना को कांस्य पदक प्राप्त हुआ। पुरुष सीनियर

फ्रीस्टाइल 57 किलोग्राम भारवर्ग में ओडिशा के अजीत भुयां को गोलड,महाराष्ट्र के परस सुभाष बिड़कर को सिल्वर, महाराष्ट्र के विकी रामचन्द्र उडके एवं हिमाचल प्रदेश के अब्दुल खान को कांस्य पदक प्राप्त हुआ। पुरुष ग्रीको रोमन सीनियर 77 किलोग्राम में झारखंड के अभिषेक मुंड ने गोलड,हिमाचल प्रदेश के अर्फन ने सिल्वर,तेलंगाना के जादव चरण एवं जम्मू-कश्मीर के इंसामम ने कांस्य पदक प्राप्त किया। पुरुष फ्रीस्टाइल सीनियर 86 किलोग्राम में हिमाचल प्रदेश के सुमित ठाकुर को गोलड, जम्मू-कश्मीर के बहादुर खान को सिल्वर, हिमाचल प्रदेश के शम्बर खान को कांस्य पदक प्राप्त किया। पुरुष ग्रीको रोमन सीनियर 130 किलोग्राम में मध्यप्रदेश के शिवा भलावी को गोलड, जम्मू कश्मीर के दिलेर खान को सिल्वर, तेलंगाना के करी राजू को कांस्य पदक प्राप्त हुआ।

अफवाह बनी आफत : बच्चा चोरी के शक में विक्षिप्त व्यक्ति की भीड़ ने की पिटाई,पुलिस ने बचाया

-संवाददाता-
एमसीबी/नागपुर,31 मार्च 2026
(घटती-घटना)।

जिले के नागपुर क्षेत्र में अफवाहों ने एक बार फिर खतरनाक रूप ले लिया। बच्चा चोरी की अपुष्ट खबर के चलते उग्र भीड़ ने एक अज्ञात व्यक्ति को पकड़कर उसकी बेरहमी से पिटाई कर दी। बाद में प्राथमिक जांच में सामने आया कि उक्त व्यक्ति मानसिक रूप से अस्वस्थ (विक्षिप्त) है और उसका किसी आपराधिक गतिविधि से कोई संबंध नहीं पाया गया है।

कैसे फैली अफवाह,कैसे भड़की भीड़ : जानकारी के अनुसार, नागपुर क्षेत्र में एक अनजान व्यक्ति के घूमने की सूचना के बाद ग्रामीणों में संदेह की स्थिति बनी। कुछ ही देर में यह संदेह अफवाह में बदल गया और बच्चा चोरी की बात तेजी से फैलने लगी। बिना किसी पुष्टि के बड़ी संख्या में लोग एकत्रित हो गए और संदिग्ध मानते हुए व्यक्ति को पकड़कर उसके साथ मारपीट शुरू कर दी।



समय पर पहुंची पुलिस, टली बड़ी घटना : घटना की सूचना मिलते ही पुलिस टीम तत्काल मौके पर पहुंची और भीड़ के बीच फसे व्यक्ति को सुरक्षित बाहर निकाला। उसे हिरासत में लेकर प्राथमिक उपचार की व्यवस्था की गई है। पुलिस द्वारा उसकी पहचान सुनिश्चित करने और पूरे घटनाक्रम की विस्तृत जांच को जा रही है।
बच्चा चोरी की नहीं हुई पुष्टि : पुलिस प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि क्षेत्र में बच्चा चोरी

जैसी किसी भी घटना की कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। प्रारंभिक तौर पर मामला पूरी तरह अफवाह पर आधारित प्रतीत हो रहा है।
दोषियों पर कार्रवाई की तैयारी : पुलिस सूत्रों के अनुसार, घटना में शामिल लोगों की पहचान की जा रही है। वीडियो फुटेज और प्रत्यक्षदर्शियों के आधार पर दोषियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। भीड़ द्वारा कानून हाथ में लेने की इस घटना को गंभीरता से लिया गया है।

प्रशासन की सख्त अपील

प्रशासन ने आम नागरिकों से अपील की है कि—
■ किसी भी अपुष्ट सूचना या अफवाह पर विश्वास न करें
■ कानून को अपने हाथ में लेने से बचें
■ संदिग्ध गतिविधि दिखने पर तत्काल डायल 112 या नजदीकी थाने को सूचना दें

खड़गवां में जाट अवैध क्रेशर गायब खनिज विभाग की चुप्पी पर उठे सवाल एक साल पहले हुई थी बड़ी कार्रवाई

-संवाददाता-
खड़गवां,31 मार्च 2026 (घटती-घटना)।

मनेंद्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर जिले के खड़गवां तहसील अंतर्गत ग्राम पंचायत पैनारी में संचालित एक अवैध क्रेशर पर लगभग एक वर्ष पूर्व प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की थी। खनिज विभाग और राजस्व विभाग की संयुक्त टीम ने मौके पर पहुंचकर क्रेशर मशीनरी, सामग्री और अन्य उपकरणों को जप्त किया था, इस दौरान संबंधित संचालक पर हजारों रुपये का जुर्माना भी लगाया गया था,अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि खनिज विभाग इस मामले में कोई ठोस कार्रवाई करेगा या यह मामला भी अन्य मामलों की तरह फाइलों में दबकर रह जाएगा।



जप्त क्रेशर रहस्यमय तरीके से गायब- कार्रवाई के बाद जाट क्रेशर को विभागीय सुपुर्दगी में रखा गया था, लेकिन अब सामने आया है कि वह मशीनरी मौके से गायब हो चुकी है,बताया जा रहा है कि लगभग एक साल से यह क्रेशर वहां मौजूद नहीं है, सबसे बड़ा सवाल यह है कि विभागीय अभिरक्षा में रखी गई इतनी बड़ी मशीनरी बिना किसी जानकारी के कैसे गायब हो गई।
एफआईआर तक नहीं,जांच भी नहीं-स्थानीय ग्रामीणों और सूत्रों के अनुसार, क्रेशर के गायब होने के बाद भी खनिज विभाग ने अब तक न तो किसी प्रकार की चोरी या गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई है और न ही किसी जिम्मेदार अधिकारी के खिलाफ जांच शुरू की गई है, इस मामले में विभाग की चुप्पी ने पूरे घटनाक्रम को और अधिक संदिग्ध बना दिया है।
सांतांठा की आशंका-ग्रामीणों के बीच यह चर्चा तेज है कि कहीं अवैध क्रेशर संचालक और विभागीय अधिकारियों के बीच मिलीभगत तो नहीं हुई,आशंका जताई जा रही है कि जाट मशीनरी को किसी अन्य स्थान पर शिफ्ट कर दिया गया या उसे बेच दिया गया, यदि ऐसा है, तो यह प्रशासनिक कार्रवाई को निष्प्रभावी बनाने का गंभीर मामला हो सकता है।

दो दिवसीय भाजपा मंडल प्रशिक्षण वर्ग का आयोजन

-संवाददाता-
लखनपुर,31 मार्च 2026
(घटती-घटना)।

भारतीय जनता पार्टी के तत्वावधान में पंडित दीनदयाल उपाध्याय महा प्रशिक्षण अभियान के अंतर्गत दो दिवसीय मंडल प्रशिक्षण वर्ग का सफल आयोजन नवीन सामुदायिक भवन में किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ ध्वजारोहण के साथ हुआ। मुख्य अतिथि के रूप में छत्तीसगढ़ शासन के मंत्री राजेश अग्रवाल तथा भाजपा जिला अध्यक्ष भरत सिंह सिंसोदिया उपस्थित रहे। मंडल अध्यक्ष दिनेश बारी सहित अनेक पदाधिकारियों ने कार्यक्रम की



गरिमा बढ़ाई। उद्घाटन सत्र में जिला अध्यक्ष भरत सिंह सिंसोदिया तथा मंत्री राजेश अग्रवाल ने कार्यक्रमों को संबोधित करते हुए पार्टी की विचारधारा, संगठन की मजबूती और आगामी रणनीतियों पर प्रकाश डाला। दोनों दिवसों में पूर्व जिला अध्यक्ष ललन प्रताप सिंह, अंबिकेश केसरी, फुलेरवरी सिंह, नितेश सिंह, धनंजय द्विवेदी, मनोज गुप्ता, राधेश्याम ठाकुर सहित कई वरिष्ठ नेताओं ने विभिन्न सत्रों

में कार्यकर्ताओं को पार्टी के इतिहास,सिद्धांत,नीतियों और संगठनात्मक कार्यप्रणाली का प्रशिक्षण दिया। कार्यक्रम में अम्बिकापुर महापौर मंजूषा भगत, जिला पंचायत अध्यक्ष निरुपा सिंह सहित अनेक वरिष्ठ पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता उपस्थित रहे। प्रशिक्षण वर्ग के दौरान रात्रि विभ्राम, भोजन एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किए गए, जिससे कार्यकर्ताओं में उत्साह का वातावरण रहा। मंडल अध्यक्ष दिनेश बारी ने बताया कि इस प्रशिक्षण ने कार्यकर्ताओं में नई ऊर्जा,उत्साह और वैचारिक स्पष्टता का संचार किया है।

बेगुनाहो को परेशान करने वाला हत्या के मामले में जेल में बंद निलंबित पूर्व कुसमी एसडीएम करुण डहरिया तीन दिन के रिमांड पर...हंसपुर कांड को लेकर आज भी लोगों में आक्रोश...

-संवाददाता-
कुसमी,31 मार्च 2026
(घटती-घटना)।

बलरामपुर-रामानुजगंज जिला के कुसमी विकास खण्ड अंतर्गत कोरंधा थाना क्षेत्र के हंसपुर गांव में आदिवासी व्यक्ति की हत्या के मामले में बेगुनाहो को परेशान करने वाला जेल में बंद आरोपित व निलंबित पूर्व कुसमी एसडीएम करुण कुमार डहरिया को पुलिस ने तीन दिनों के रिमांड पर लिया है। इस घटनाक्रम के बाद क्षेत्र में एक बार फिर हलचल तेज हो गई है और स्थानीय ग्रामीणों में आक्रोश का माहौल बना हुआ है। मिली जानकारी के अनुसार,पुलिस ने आरोपी पूर्व एसडीएम कुसमी को रिमांड पर लेने के



बाद कुसमी नगर के मुख्य मार्ग से न ले जाकर बाईपास सड़क का रास्ता चुना। बताया जा रहा है कि पुलिस ने यह कदम संभावित विरोध और भीड़ से बचने के लिए उठाया। हालांकि इस कार्रवाई को



लेकर लोगों में तरह-तरह की चर्चाएं भी हो रही हैं। हंसपुर में हुए इस बहुचर्चित हत्या कांड को लेकर ग्रामीणों में पहले से ही नाराजगी बनी हुई है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि आरोपित उक्त अधिकारी के कार्यकाल के दौरान कई विवादित गतिविधियाँ सामने आई थीं,जिनकी निष्पक्ष

जांच की मांग लगातार उठती रही है। अब हत्या के मामले में गिरफ्तारी और रिमांड के बाद लोगों की उम्मीदें जांच पर टिकी हुई हैं। वर्तमान में इस पूरे मामले की विवेचना कोरंधा थाना में चल रही है, जिसकी जांच एसडीओपी कुसमी आशीष कुंजाम द्वारा की जा रही है। पुलिस रिमांड के दौरान आरोपित से गहन पूछताछ कर घटना से जुड़े सभी पहलुओं को खंगालने की तैयारी में है। सूत्रों के अनुसार, इस दौरान कई महत्वपूर्ण खलासे होने की संभावना जताई जा रही है। इधर,क्षेत्र के ग्रामीणों और जनप्रतिनिधियों ने मामले की निष्पक्ष और पारदर्शी जांच की मांग की है,ताकि दोषि आरोपित व निलंबित पूर्व एसडीएम करुण कुमार डहरिया को

ढोढ़केसोरा-डंडकेसरा को जोड़ेगी नई पक्की सड़क: लुंडा विधायक प्रबोध मिंज ने दिलाई 14.45 करोड़ की स्वीकृति

-संवाददाता-
लखनपुर,31 मार्च 2026
(घटती-घटना)।

वनांचल क्षेत्र में विकास की नई बयार, विधायक प्रबोध मिंज ने सबसे लुंडा विधानसभा क्षेत्र की जिम्मेदारी संभाली है,विधानसभा क्षेत्र कुन्नी का यह वनांचल इलाका विकास के नए आयाम छू रहा है। क्षेत्र की जनता की लंबित मांग को पूरा करते हुए विधायक ने बहुप्रतीक्षित ढोढ़केसोरा से डंडकेसरा तक 7.10 किलोमीटर पक्की सड़क निर्माण की स्वीकृति दिलाई है। इस परियोजना पर कुल 14 करोड़ 45 लाख 64 हजार रुपये की राशि स्वीकृत हुई है। सड़क की स्वीकृति मिलते ही पूरा क्षेत्र वासी विधायक का आभार जता रहे हैं प्रायः सभी प्रमुख सड़कों की स्वीकृति दिलाई जा चुकी है और निर्माण कार्य भी तेजी से शुरू हो गए हैं। जो क्षेत्र कभी पहुंच से वंचित माना जाता था, वह आज मुख्य मार्गों से जुड़कर अपनी समस्याओं से उबर रहा है। यह नई सड़क न केवल स्थानीय क्षेत्र को जोड़ेगी।



सख्त सजा मिल सके और पीड़ित परिवार को न्याय मिल सके। हालांकि बलरामपुर - रामानुजगंज जिला के पुलिस कप्तान एसपी वैभव बैकर ने स्पष्ट रूप से बयान दिया है की इस मामले में कोई भी दोसरी बक्सा नहीं जायेगा, तथा एसपी वैभव बैकर ने इस पूरे मामले में अपनी पैनी नजर जमाए रखी है। जिनके आदेश के परिपालन में तत्कालीन कोरंधा थाना प्रभारी अमर सिंह कोमरे ने घटना की सूचना मिलते ही तत्पराता दिखाते हुए आरोपियों को पकड़ने में सफलता हासिल कर 24 घंटे के अंदर न्यायाधिक रिमांड पर जेल दाखिल कर दिया था, जिसे लेकर बलरामपुर पुलिस को सराहनीय कदम बताया गया है।

संभागीय साहू सम्मेलन में अत्यवस्था, खाली कुर्सियां, मंच विवाद और नेतृत्व पर सवाल, कुर्सी खाली, मंच भरा- सम्मेलन को किसका चला 'रिमोट' ?

संभागीय साहू समाज सम्मेलन : भव्यता के बीच अत्यवस्था, खाली कुर्सियां, मंच विवाद और अंदरूनी असंतोष की पूरी तस्वीर



सम्मेलन में स्वागत कम, व्यवस्था ज्यादा सवालों में...

भव्य आयोजन या अत्यवस्था का मंच? साहू समाज सम्मेलन पर उठे सवाल

कुर्सी के लिए जद्दोजहद, नेतृत्व रहा नदारद!



—संवाददाता—
सूरजपुर/कोरिया, 31 मार्च 2026
(घटती-घटना)।
सूरजपुर संभाग के साहू समाज का सूरजपुर में आयोजित संभागीय सम्मेलन इस बार केवल एक सामाजिक आयोजन तक सीमित नहीं रहा, बल्कि व्यवस्थाओं की कमी, नेतृत्व पर सवाल, मंच विवाद और अंदरूनी असंतोष के कारण व्यापक चर्चा का विषय बन गया। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की उपस्थिति ने इसे राजनीतिक और प्रशासनिक दृष्टि से महत्वपूर्ण बना दिया, लेकिन आयोजन के दौरान और बाद में सामने आई स्थितियों ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। संभागीय स्तर के इस सम्मेलन को लेकर समाज के भीतर काफी उत्साह और उम्मीद थी कि बड़ी संख्या में लोग शामिल होंगे और यह एकजुटता का संदेश देगा, लेकिन कार्यक्रम स्थल पर अपेक्षित भीड़ नहीं पहुंच पाई, पंडाल में कई स्थानों पर कुर्सीयां खाली नजर आईं, जो आयोजन की तैयारी और सहायिता दोनों पर प्रश्नचिह्न खड़ा करती हैं, संभाग के विभिन्न जिलों से व्यापक भागीदारी की उम्मीद थी, लेकिन वास्तविक उपस्थिति उस स्तर की नहीं रही, जिससे आयोजन का प्रभाव सीमित नजर आया।

नेतृत्व के हिस्से की जिम्मेदारियों में समन्वय की कमी साफ नजर आई, यह आयोजन एक ओर सरकारी उपस्थिति से सुसज्जित था, तो दूसरी ओर समाज के नेतृत्व द्वारा संचालित होना था, यही दोहरी व्यवस्था कई जगह पर असंतुलन का कारण बनी, जिससे व्यवस्थाओं में कमी देखने को मिली।

मूलभूत सुविधाओं में कमी : पानी और बैठने की व्यवस्था पर सवाल

कार्यक्रम में शामिल लोगों ने सबसे पहले पानी और बैठने की व्यवस्था को लेकर असंतोष जताया। दूर-दराज से आए समाज के लोगों को पर्याप्त पानी नहीं मिल पाया और कई लोग बैठने के लिए जगह खोजते रहे, पंडाल के अंदर और बाहर अत्यवस्था का माहौल रहा, जिससे यह संदेश गया कि आयोजन की योजना और क्रियान्वयन में खामियां रह गईं, यह स्थिति विशेष रूप से तब अधिक गंभीर लगती है, जब कार्यक्रम में बड़ी संख्या में अतिथि और वरिष्ठ पदाधिकारी शामिल थे।

मंच व्यवस्था बना सबसे बड़ा विवाद

पुरे आयोजन का सबसे चर्चित और संवेदनशील मुद्दा मंच व्यवस्था को लेकर रहा, आरोप है कि मंच पर स्थान वितरण में संतुलन नहीं रखा गया और कई महत्वपूर्ण पदाधिकारियों को जगह नहीं मिल पाई, कोरिया साहू समाज के जिलाध्यक्ष जगदीश साहू के साथ हुई घटना ने इस विवाद को और बढ़ा दिया, बताया गया कि मंच पर सभी कुर्सीयां पर नाम लिखे गए थे, लेकिन उनके नाम की कुर्सी नहीं थी, उन्होंने मंच पर जगह पाने के लिए प्रयास किया, लेकिन सफल नहीं हो सके, यहां तक कि स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल द्वारा भी कुर्सी लगाने के निर्देश दिए गए, फिर भी व्यवस्था नहीं की गई, अंततः उन्हें मंच छोड़कर नीचे बैठना पड़ा यह घटना न केवल व्यक्तिगत अपमान के रूप में देखी गई, बल्कि इसे पूरे कोरिया जिले के प्रतिनिधित्व से जोड़कर भी देखा गया।

परिवारवाद और पक्षपात के आरोप

मंच व्यवस्था को लेकर यह भी आरोप सामने आया कि पूर्व जिलाध्यक्ष और उनके परिवार को प्रमुख स्थान दिया गया, जबकि कई वरिष्ठ और वर्तमान पदाधिकारियों को नजरअंदाज किया गया, समाज के भीतर यह चर्चा भी रही कि मंच पर वही चेहरे प्रमुख थे, जिनकी राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं हैं, इससे यह सवाल उठने लगा कि क्या सामाजिक मंच का उपयोग राजनीतिक लाभ के लिए किया जा रहा है, परिवारवाद शब्द भी इस पूरे आयोजन के संदर्भ में बार-बार सामने आया, जिससे समाज के भीतर असंतोष और बढ़ गया।

सोशल मीडिया पर खुलकर सामने आया आक्रोश

कार्यक्रम समाप्त होने के बाद समाज के क्लट्स पर समूहों में असंतोष खुलकर सामने आया, लोगों ने पोस्ट और संदेशों के माध्यम से अपनी नाराजगी व्यक्त की, कुछ लोगों ने यह भी लिखा कि मेहनत पूरे समाज ने की, लेकिन फायदा कुछ लोगों को ही मिला, यह प्रतिक्रिया इस बात का संकेत है कि असंतोष केवल आयोजन तक सीमित नहीं रहा, बल्कि समाज के भीतर गहराई तक पहुंच गया है।

आर्थिक पहलू: चंद और घोषणा के बाद की स्थिति

कार्यक्रम को लेकर चंद संग्रह की चर्चा भी सामने आई, समाज के भीतर यह सवाल उठ रहा है कि जो राशि एकत्रित की गई, उसका उपयोग किस प्रकार किया गया और क्या उसका सही हिस्सा सामने आया, इसी बीच मुख्यमंत्री द्वारा सूरजपुर साहू समाज को 50 लाख रुपये छात्रावास निर्माण और 25 लाख रुपये बाइडी वॉल के लिए दिए जाने की घोषणा भी चर्चा का विषय बनी, बताया जा रहा है कि इस घोषणा के बाद कोरिया साहू समाज की ओर से अपेक्षित प्रतिक्रिया नहीं आई, न तो सार्वजनिक बधाई संदेश सामने आया और न ही कोई उत्साहपूर्ण प्रतिक्रिया दिखी, जिससे समाज के भीतर अलग तरह की स्थिति उत्पन्न हो गई।

कोरिया जिले की सीमित भागीदारी

कोरिया जिले की भागीदारी को लेकर भी सवाल उठे हैं, जानकारी के अनुसार कार्यक्रम के बहुत कम सदस्य कार्यक्रम में पहुंचे, कुल गिलाकर लगभग 20 लोगों की उपस्थिति बताई जा रही है, कार्यक्रम स्थल पर कोरिया जिले के बैनर-पोस्टर भी नजर नहीं आए, इससे यह संदेश गया कि कोरिया जिले की भागीदारी अपेक्षाकृत कमजोर रही, जो संभागीय स्तर के आयोजन के अनुरूप नहीं थी।

नेतृत्व की भूमिका और रिमोट कंट्रोल की चर्चा

इन सभी घटनाओं के बाद समाज के भीतर यह चर्चा भी सामने आई कि कार्यक्रम का संचालन वास्तविक नेतृत्व के बजाय रिमोट कंट्रोल से किया जा रहा था, कुछ लोगों का कहना है कि वर्तमान जिलाध्यक्ष सक्रिय भूमिका में नजर नहीं आए, निर्णय किसी अन्य के प्रभाव में लिए गए, नेतृत्व की स्पष्टता और जवाबदेही नहीं दिखी यह स्थिति समाजवादी कमजोरी की ओर इशारा करती है।

सामाजिक एकता के मंच पर उमरी दरार

सूरजपुर में आयोजित यह संभागीय सम्मेलन एक बड़े सामाजिक आयोजन के रूप में सामने आया, लेकिन व्यवस्थाओं की कमी, मंच विवाद, नेतृत्व पर सवाल और अंदरूनी असंतोष ने इसकी छवि को प्रभावित किया है, यह आयोजन जहां एकता का संदेश देने का अवसर था, वहीं कई मामलों में विभाजन और असंतोष की तस्वीर सामने आई, भविष्य में ऐसे आयोजनों को सफल बनाने के लिए पारदर्शी व्यवस्था, सभी को समाज अवसर, बेहतर समन्वय और स्पष्ट नेतृत्व पर विशेष ध्यान देना आवश्यक होगा।

डिस्क्लेमर-

यह समाचार स्थानीय स्रोतों, प्रतिभागियों के अनुभवों, सोशल मीडिया पोस्ट और क्षेत्रीय चर्चाओं के आधार पर तैयार किया गया है, इसमें शामिल कुछ आरोपों की स्वतंत्र आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, संबंधित पक्षों की प्रतिक्रिया प्राप्त होने पर समाचार को अद्यतन किया जाएगा।

जिला अस्पताल में मंत्री लक्ष्मी का औचक निरीक्षण, अत्यवस्था पर जताई नाराजगी

—संवाददाता—
सूरजपुर, 31 मार्च 2026
(घटती-घटना)।

जिले के जिला चिकित्सालय का आज मंत्री लक्ष्मी ने आकस्मिक निरीक्षण किया, निरीक्षण के दौरान वे सीधे महिला वाई पहुंचीं, जहां भर्ती मरीजों से उनका हालचाल जाना और उपचार की स्थिति के बारे में जानकारी ली, इस दौरान उन्होंने मरीजों से अस्पताल की सुविधाओं और व्यवस्थाओं को लेकर फीडबैक भी लिया, मंत्री के इस औचक निरीक्षण ने अस्पताल की व्यवस्थाओं की वास्तविक स्थिति उजागर कर दी, अब देखने वाली बात होगी कि दिए गए निर्देशों का कितना अमल होता है और मरीजों को बेहतर सुविधाएं मिल पाती हैं या नहीं।



पर ही अस्पताल प्रबंधन को फटकार लगाई, उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि मरीजों के साथ किसी भी प्रकार का दुर्व्यवहार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

लापरवाह कर्मचारियों पर कार्रवाई के निर्देश

मंत्री ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि यदि किसी भी कर्मचारी की लापरवाही सामने आती है तो उस पर तत्काल कार्रवाई की जाए, उन्होंने कहा कि अस्पताल जैसी संवेदनशील जगह पर कार्यरत कर्मचारियों को अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए और मरीजों के साथ मानवीय व्यवहार करना चाहिए।

सियासत में सौहार्द की नई इबारत डॉ. महंत ने की मंत्री श्याम बिहारी की तारीफ

चिरमिरी से मनेन्द्रगढ़ तक गूँजी क्षेत्रीय गौरव की गूँज

—संवाददाता—
कोरिया, 31 मार्च 2026
(घटती-घटना)।

राजनीति के अखाड़े में अक्सर वैचारिक तलवारें खिंची रहती हैं, लेकिन जब धरातल पर क्षेत्रीय अस्मिता और विकास का प्रश्न आता है, तो छत्तीसगढ़ की माटी के सपूत दलगत सीमाओं को लांघकर अपनत्व का परिचय देना बखूबी जानते हैं। पिछले दो दिनों से मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर क्षेत्र की फिजाओं में सियासी कड़वाहट के बजाय एक ऐसी आत्मीयता घुली है, जिसने पूरे प्रदेश का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। कल चिरमिरी के पावन मंदिर परिसर में स्वास्थ्य मंत्री श्यामबिहारी जायसवाल और नेता प्रतिपक्ष डॉ. चरणदास महंत के बीच हुई शिष्टाचार भेंट ने जो बीज बोया था, उसकी मिठास आज मनेन्द्रगढ़ में डॉ. महंत के शब्दों में स्पष्ट सुनाई दी।



हाल ही में सूरजपुर अस्पताल के निरीक्षण के दौरान कैबिनेट मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े की नाराजगी और स्वास्थ्य व्यवस्थाओं पर उनके द्वारा उठाए गए सवालों के बाद कयास लगाए जा रहे थे कि विपक्ष इस मुद्दे पर सरकार को घेरगा। किंतु, राजनीति के चाणक्य कहे जाने वाले डॉ. चरणदास महंत ने एक अप्रत्याशित रुख अपनाते हुए स्वास्थ्य मंत्री का बचाव किया। मीडिया से मुखातिब होते हुए डॉ. महंत ने बड़े ही बेबाक और गर्व भरे अंदाज में कहा- श्यामबिहारी जायसवाल केवल एक मंत्री नहीं, बल्कि हमारे अपने क्षेत्र के उर्जावान प्रतिनिधि हैं। मैं स्पष्ट रूप से मानता हूँ कि हमारा मंत्री उत्कृष्ट कार्य कर रहा है। जिसे ईर्ष्या होगी, वही उनकी आलोचना करेगा, हम तो उनके कर्मठ नेतृत्व और विकास कार्यों के साथ पूरी मजबूती से खड़े हैं।

अंतर्कलह पर विराम-जहाँ एक ओर भाजपा के भीतर से ही (लक्ष्मी राजवाड़े के माध्यम से) स्वास्थ्य विभाग पर उंगलियाँ उठी थीं, वहीं विपक्ष के सबसे कट्टर नेता ने जायसवाल को क्लीन चिट देकर उनकी स्थिति को और अधिक सुदृढ़ कर दिया है। डॉ. महंत ने यह संदेश दे दिया है कि एमसीबी क्षेत्र के विकास के लिए वे वैचारिक मतभेदों को किनारे रखकर अपने क्षेत्र के मंत्री का मनोबल बढ़ाने से पीछे नहीं हटेंगे।

कार्यालय पंजीयक लोक न्याय अनुविभाग अम्बिकापुर सरगुजा, छ.ग.ग.

प्रारूप-चार (नियम 5 (1) देखिए)
छत्तीसगढ़ लोक न्याय अधिनियम 1951 (1951 का 30) की धारा 5 की उपधारा (2) तथा छत्तीसगढ़ लोक न्याय नियम 1962 के नियम 5 का उप नियम (1) देखिए।
अम्बिकापुर दिनांक 12/03/2026
कमांक 779 / वाचक- 1 / 2026 यह कि आवेदक संतोष सिंह आ० स्व० बी.डी. सिंह, सचिव श्री महावीर सेवा समिति डी.सी. रोड अम्बिकापुर तहसील अम्बिकापुर जिला सरगुजा (छ.ग.ग.), ने छ.ग.ग. लोक न्याय अधिनियम 1951 (1951 का 30) की धारा 4 के अधीन अनुसूची में लोक न्याय की तरह विनिर्दिष्ट की गई सम्पत्ति के पंजीयन के लिए आवेदन किया है। एतद् द्वारा सूचना दी जाती है कि आवेदन मेरे न्यायालय में दिनांक 13/04/2026 को विचार के लिए लिया जाएगा।
अतः मैं फोगेश सिन्हा, अनुविभाग अम्बिकापुर के लोक न्यायों के पंजीयक अपने न्यायालय में दिनांक 13/04/2026 को उक्त अधिनियम की धारा 5 की उपधारा (1) में अपेक्षित जांच करना प्रस्तावित करता हूँ। अतः एतद् द्वारा सूचना दी जाती है कि उक्त न्याय या सम्पत्ति का कोई न्यायसंधारी या कार्यकारी न्यायसंधारी या उसमें हित रखने वाले और किसी मत या सुझाव प्रस्तुत करने का विचार रखने वाले व्यक्ति को इस सूचना के प्रकाशन के दिनांक से एक माह के भीतर दो प्रतियों में लिखित कथन प्रस्तुत करें और मेरे न्यायालय में सम्मक्ष में उपरोक्त दिनांक को या तो व्यक्तिगत या अभिभाषक या अभिभक्तों के द्वारा उपस्थित होना चाहिए। उपरोक्त अवधि समाप्त होने के पश्चात आपत्तियों को विचार के लिए ग्रहण नहीं किया जावेगा।
-अनुसूची-
(लोक न्याय का नाम पता व सम्पत्ति का विवरण)
लोक न्याय का नाम व पता - श्री महावीर सेवा समिति सार्वजनिक न्याय, पता-श्री हनुमान मन्दिर परिसर, डी.सी. रोड अम्बिकापुर तहसील - अम्बिकापुर जिला सरगुजा (छ.ग.ग.)
2. जिला - सरगुजा
3. चाल सम्पत्ति - निरक
4. अचल सम्पत्ति - निरक
जारी दिनांक 12/03/2026
(फोगेश सिन्हा)
पंजीयक लोक न्याय अनुविभाग अम्बिकापुर

न्यायालय नायाव तहसीलदार दरिमा जिला-सरगुजा, छ.ग.ग.

ईशतहार
रा.प्र.क./ /अ-6/25-26
ग्राम कंठी तहसील दरिमा
एतद् द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता कि आवेदक ओमप्रकाश राजवाड़े आ० बेसाहू राम जाति रजवार निवासी ग्राम कंठी थाना व तहसील दरिमा जिला सरगुजा छ.ग.ग. के द्वारा ग्राम कंठी पहलु० 03 रा०नि० 115/2 सोहाहा तहसील दरिमा में स्थित भूमि ख०न० 100/1, 105/2, 110, 110, 122/1, 156, 164, 165, 221/2, 222/2, 323, 558, 1257/2, 1258/2, 1259, 1263 रकबा 0.129, 0.234, 0.125, 0.821, 0.340, 0.291, 0.113, 0.077 हे० भूमि का बी-1 एवं वर्तमान भूमि स्वामी रामप्रसाद राजवाड़े पिता मनबसन की मृत्यु प्रमाण पत्र, आधार कार्ड तथा दिनांक 02/04/2025 को की गयी पंजीकृत वसीयत नामा (अंतिम इच्छा-पत्र) की छाया प्रति संतुलन कर अपंजीकृत वसीयत नामा (अंतिम इच्छा-पत्र) के आधार पर वाद भूमि में से आवेदक के दादा रामप्रसाद को प्राप्त उसकी हिस्से की भूमि पर से राजस्व अधिलेख में मृतक का नाम विलोपित कर आवेदक का नाम दर्ज करने हेतु आवेदन प्राप्त है।
अतः उपरोक्त संबंध में जिस किसी व्यक्ति को कोई आपत्ति हो तो वे स्वयं या अपने अधिवक्ता के माध्यम से जारी दिनांक से 15 दिवस के भीतर अपना दावा आपत्ति प्रस्तुत कर सकते हैं। नियत तिथि के उपरांत किसी भी प्रकार का दावा / आपत्ति प्राप्त होने पर पर विचार नहीं किया जावेगा।
आज दिनांक 10/03/2026 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालयीन पद मुद्रा द्वारा जारी।
नायाव तहसीलदार दरिमा, सरगुजा
(सील)

न्यायालय अतिरिक्त तहसीलदार अम्बिकापुर, जिला सरगुजा, छ.ग.ग.

ईशतहार
रा.प्र.क. /अ-6/2025-26
एतद् द्वारा सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि आवेदिका रंगमते आ० महेन्द्र पति छत्रसया, निवासी ग्राम परसा, तहसील अम्बिकापुर, जिला सरगुजा छ.ग.ग. के द्वारा ग्राम परसा स्थित भूमि खसरा नंबर 36/1, 36/18, 370/1, 2167/1, 2168/1, 2169/1 कुल खसरा नंबर 06 कुल रकबा 1.1950 हे० के वर्तमान भूमि स्वामी स्व. महेन्द्र आ. चमर उर्फ बबोलन की मृत्यु होने के कारण उनके विधिवत वारिशां के नाम पर फौती नामांतरण दर्ज कराने बावजू आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है।
उक्त संबंध में किसी व्यक्ति अथवा संस्था को कोई आपत्ति हो तो पेशी दिनांक 9/04/2026 को न्यायालय में स्वयं अथवा अपने अभिभाषक के माध्यम से उपस्थित होकर दावा आपत्ति प्रस्तुत कर सकते हैं। समय सीमा के बाद प्राप्त दावा आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।
आज दिनांक 17/3/2026 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालयीन पदमुद्रा से जारी।
अतिरिक्त तहसीलदार अम्बिकापुर-2
(सील)

न्यायालय तहसीलदार लखनपुर, जिला सरगुजा, छ.ग.ग.

ईशतहार
लखनपुर दिनांक 25.03.2026
एतद् द्वारा आम जनता ग्राम बगदरी को सूचित किया जाता है कि आवेदक बनेश्वर आ.स्व. श्री धनराज निवासी ग्राम बगदरी के द्वारा अपने पिता स्व. श्री धनराज की दिनांक 10.05.1998 को मृत्यु होना बताते हुए जन्म/मृत्यु रजिस्ट्रिकरण अधिनियम 1969 की धारा 13 (3) एवं छ.ग. जन्म मृत्यु रजि. नियम 2001 के नियम 9 नियम (3) के तहत आवेदन द्वारा मृत्यु प्रमाण पत्र हेतु आवेदन सूचना प्रस्तुत किया है। जिस पर दिनांक 09.04.2026 को सुनवाई की जानी है।
आवेदक के द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र में किसी को कोई आपत्ति हो तो वो न्यायालय की पेशी, 09.04.2026 तक अपना दावा / आपत्ति पेश कर सकते हैं। नियत तिथि के पश्चात प्राप्त दावा आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।
तहसीलदार अम्बिकापुर, सरगुजा
(सील)

कोरिया मॉडल पर सवाल, जल योजना या नया नाम

5% मॉडल 100% बहस



मन की बात में कोरिया मॉडल: जल संरक्षण की सफलता या अधूरी तस्वीर?
मोर गांव, मोर पानी बनाम आवा पानी झोंकी: समान उद्देश्य, अलग दावे, कई सवाल
कोरिया का 5 प्रतिशत जल मॉडल चर्चा में: जमीनी हकीकत और दावों के बीच अंतर
जल संरक्षण की दो योजनाएं, एक बहस: क्या नया है कोरिया मॉडल में?
मन की बात में सराहना, जमीन पर सवाल, कोरिया जल मॉडल की पड़ताल

-रवि सिंह-

कोरिया, 31 मार्च 2026
(घटती-घटना)।

छत्तीसगढ़ में जल संरक्षण को लेकर पिछले कुछ वर्षों में कई स्तरों पर पहलें शुरू हुई हैं, वर्ष 2022 में राज्य सरकार द्वारा शुरू किया गया मोर गांव, मोर पानी अभियान और वर्ष 2025 में कोरिया जिले में प्रारंभ हुई आवा पानी झोंकी योजना, जिसे बाद में 5 प्रतिशत जल संरक्षण मॉडल के रूप में प्रचारित किया गया, अब एक साथ चर्चा के केंद्र में हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम में कोरिया मॉडल का उल्लेख होने के बाद यह बहस और तेज हो गई है कि क्या यह वास्तव में एक नया और प्रभावी मॉडल है या पहले से चल रही योजना का ही परिवर्तित रूप है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम में कोरिया जिले के 5 प्रतिशत जल संरक्षण मॉडल को उदाहरण के रूप में प्रस्तुत किए जाने के बाद अब इस मॉडल की जमीनी सच्चाई को लेकर सवाल उठने लगे हैं, स्थानीय स्तर पर चर्चा इस बात को लेकर है कि कार्यक्रम में दिखाए गए दृश्य और वास्तविक स्थिति में काफी अंतर दिखाई दे रहा है। बताया जा रहा है कि जिले में 5 प्रतिशत मॉडल के तहत कई ग्राम पंचायतों के किसानों के खेतों में बनाए गए गड्ढों का कार्य हाल ही में, लगभग 20 से 25 दिनों के भीतर कराया गया है, ऐसे में वर्तमान समय में, जब ग्रीष्म ऋतु की शुरुआत हो चुकी है और हाल के दिनों में वर्षा नहीं हुई है, तो इन गड्ढों में पानी भरा हुआ दिखाना सवालों के घेरे में आ गया है, स्थानीय लोगों का कहना है कि जब जिले के बड़े तालाब, नदी और जल स्रोत सूखने की स्थिति में हैं, तब छोटे आकार के गड्ढों में जल भराव का दृश्य वास्तविकता से मेल नहीं खाता, इसी आधार पर यह सवाल उठ रहा है कि क्या प्रस्तुत किए गए वीडियो और चित्र हलिया हैं या पुराने हैं?

मन की बात में उल्लेख और राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने कार्यक्रम मन की बात के 132 वें एपिसोड में कोरिया जिले के इस मॉडल का उल्लेख करते हुए इसे जनभागीदारी आधारित जल संरक्षण का उदाहरण बताया, उन्होंने कहा कि जिले के किसान अपने खेतों के एक हिस्से में सोखता गड्ढा बनाकर भूजल स्तर सुधारने का प्रयास कर रहे हैं, इस उल्लेख के बाद यह योजना राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा में आ गई और इसे एक सफल प्रयोग के रूप में प्रस्तुत किया गया, लेकिन इसी के साथ स्थानीय स्तर पर सवाल भी उठने लगे कि क्या यह मॉडल वास्तव में उतना प्रभावी और व्यापक है, जितना प्रस्तुत किया जा रहा है।



अंतर चार्ट: मोर गांव, मोर पानी बनाम आवा पानी झोंकी

बिंदु	मोर गांव, मोर पानी	आवा पानी झोंकी (5 प्रतिशत मॉडल)
शुरुआत	22 मार्च 2022	मार्च 2025
स्तर	राज्य स्तरीय	जिला स्तरीय (कोरिया)
सहयोग	यूनिसेफ + जल जीवन मिशन	जिला प्रशासन
उद्देश्य	जल संरक्षण + जागरूकता	खेत आधारित जल संरक्षण + कृषि
कार्यक्षेत्र	पूरे राज्य में	कोरिया जिला
कार्यप्रणाली	घर/गांव आधारित	खेत आधारित (5 प्रतिशत क्षेत्र)
तकनीक	जीआईएस, जलदूत ऐप	सीमित/स्थानीय
जनभागीदारी	व्यापक	मिश्रित/विवादित
प्रमुख गतिविधि	सोखता गड्ढे, वृक्षारोपण	खेतों में गड्ढे
प्रभाव	दीर्घकालीन	मूल्यांकनाधीन

आंकड़ों और दावों पर उठते प्रश्न

प्रशासन की ओर से इस योजना के तहत बड़ी संख्या में किसानों की भागीदारी और जल स्रोतों में वृद्धि जैसे दावे किए गए हैं, हालांकि, इन आंकड़ों के आधार और वैज्ञानिक प्रमाणों को लेकर स्पष्टता नहीं है, विशेषज्ञों का मानना है कि भूजल स्तर में किसी भी प्रकार की वृद्धि का आकलन करने के लिए लंबी अवधि की निगरानी आवश्यक होती है, एक वर्ष से कम समय में जल स्तर में वृद्धि का दावा करना सटीक निष्कर्ष नहीं माना जा सकता, इसके अलावा, गड्ढों के निर्माण की संख्या और उनके वास्तविक प्रभाव का कोई विस्तृत सार्वजनिक डेटा उपलब्ध नहीं होने से भी स्थिति स्पष्ट नहीं हो पाई है।

जमीनी स्थिति: दावे और वास्तविक अनुभव

योजना को लेकर जमीनी स्तर पर मिश्रित प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं, कुछ लोग इसे सकारात्मक पहल मानते हैं और भविष्य में इसके लाभ की संभावना देखते हैं, वहीं कई किसानों और ग्रामीणों ने इसके क्रियान्वयन को लेकर सवाल उठाए हैं, स्थानीय स्तर पर यह भी कहा जा रहा है कि गड्ढों का निर्माण हर जगह पूरी तरह स्वैच्छिक नहीं था और कुछ मामलों में प्रशासनिक दबाव की बात भी सामने आई है, कुछ किसानों का कहना है कि उन्हें अपने खर्च पर गड्ढे खुदवाने पड़े, जबकि योजना को जनभागीदारी आधारित बताया गया है, इसके अलावा यह भी सवाल उठ रहा है कि खेतों में बनाए गए बड़े गड्ढों से नमी कितने समय तक बनी रहेगी और क्या यह वास्तव में कृषि उत्पादकता बढ़ाने में मदद करेगा।

भूजल संरक्षण के लिए दीर्घकालीन उपायों की आवश्यकता

जल संरक्षण को लेकर प्रधानमंत्री द्वारा मन की बात में रूफ वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम को एक प्रभावी उपाय बताया गया है, इस संदर्भ में स्थानीय स्तर पर यह राय सामने आ रही है कि यदि वास्तव में भूजल स्तर को बढ़ाना है, तो पारंपरिक और वैज्ञानिक दोनों उपायों को प्राथमिकता देनी होगी, कोरिया जिले में पहले बड़ी संख्या में तालाब और कुएं मौजूद थे, जो वर्षा जल को संग्रहित कर धीरे-धीरे भूजल स्तर को बढ़ाने में सहायक होते थे, लेकिन समय के साथ इनका संरक्षण नहीं हो सका, कई स्थानों पर तालाबों को पाट दिया गया, वहीं कई कुएं उपयोग के अभाव में समाप्त हो गए, ऐसे में यह मांग उठ रही है कि जो जल स्रोत अभी भी बचे हुए हैं, उनका संरक्षण और पुनर्जीवन प्राथमिकता के आधार पर किया जाए, साथ ही, शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में रूफ वाटर हार्वेस्टिंग को अनिवार्य रूप से लागू करने की दिशा में ठोस नीति बनाई जाए।

कोरिया में आवा पानी झोंकी: स्थानीय पहल या नया मॉडल?

इसी दौरान मार्च 2025 में कोरिया जिले में कलेक्टर संजय चंदन त्रिपाठी के नेतृत्व में आवा पानी झोंकी नामक एक नई पहल शुरू की गई, इस योजना का मुख्य उद्देश्य खेतों में ही वर्षा जल को रोककर भूजल स्तर को बढ़ाना और कृषि उत्पादकता में सुधार करना बताया गया, इस मॉडल के तहत किसानों को अपने खेत के लगभग 5 प्रतिशत हिस्से में गड्ढे बनाने के लिए प्रेरित किया गया, ताकि वर्षा जल खेत में ही ठहर सके और धीरे-धीरे जमीन में समाहित हो सके, बाद में इस पहल को 5 प्रतिशत जल संरक्षण मॉडल के नाम से प्रचारित किया गया, जिससे इसे एक विशिष्ट और अलग पहचान दी जा सके, योजना में पारंपरिक जल स्रोतों जैसे कुओं और छोटे तालाबों के पुनर्जीवन की बात भी शामिल की गई, साथ ही महिलाओं की भागीदारी को भी महत्वपूर्ण बताया गया, क्योंकि ग्रामीण जल प्रबंधन में उनकी भूमिका प्रमुख होती है।

मन की बात में कोरिया मॉडल:

जल संरक्षण की सफलता या अधूरी तस्वीर?

'मोर गांव, मोर पानी' अभियान (राज्यस्तरीय)

शुरुआत: 22 मार्च 2022 (विश्व जल दिवस)
संस्था: यूनिसेफ + जल जीवन मिशन

- मुख्य उद्देश्य**
वर्षा जल संयोजन, भूजल स्तर सुधार, ग्रामीण विकास, जल जागरूकता
- प्रमुख कार्य**
सोखता गड्ढे, दीवार लेखन, बोरो बंधन, वृक्षारोपण
- कार्यक्षेत्र**
छत्तीसगढ़ के सभी जिले
- 2025 में बढ़त**
GIS तकनीक और 'जलदूत' ऐप से जल स्तर की निगरानी

'आवा पानी झोंकी' (5% जल संरक्षण मॉडल) (कोरिया जिला)

शुरुआत: मार्च 2025 (कलेक्टर संजय चंदन त्रिपाठी की पहल)

- मुख्य उद्देश्य**
खेतों में वर्षाजल रोकना, भूजल रिचार्ज, मिट्टी की नमी बनाए रखना, कृषि उत्पादकता बढ़ाना
- कार्यप्रणाली**
खेत के 5% हिस्से में गड्ढे, जल संयोजन संरचनाएं, पारंपरिक स्रोतों का पुनर्जीवन: तालाब, कुएं
- महिलाओं की भूमिका**
जल प्रबंधन में सहभागिता पर विशेष जोर

मोर गांव, मोर पानी : राज्य स्तरीय अभियान की शुरुआत और विस्तार

छत्तीसगढ़ में जल संकट और भूजल स्तर में गिरावट को देखते हुए 22 मार्च 2022, विश्व जल दिवस के अवसर पर मोर गांव, मोर पानी अभियान की शुरुआत की गई थी, यह अभियान यूनिसेफ के सहयोग से जल जीवन मिशन के तहत संचालित किया गया और इसे राज्य के सभी जिलों में लागू किया गया, इस अभियान का उद्देश्य वर्षा जल के संरक्षण, उपयोग किए गए पानी के प्रबंधन और भूजल स्तर में सुधार के माध्यम से दीर्घकालीन जल सुरक्षा सुनिश्चित करना था, इसके तहत ग्रामीणों की भागीदारी से घरों, स्कूलों व कार्यालयों में हेडपंप के सामने सोखता गड्ढे बनाए गए, खेतों के माध्यम से जल साक्षरता बढ़ाई गई और पारंपरिक जल संरक्षण तकनीकों जैसे बोरो बंधन को प्रोत्साहित किया गया, वर्ष 2025 में इस अभियान को और गति देने के लिए तकनीकी हस्तक्षेप भी जोड़े गए, जीआईएस तकनीक और जलदूत ऐप के माध्यम से जल स्तर की निगरानी शुरू की गई, जिससे यह अभियान केवल जागरूकता तक सीमित न रहकर डेटा आधारित निगरानी की दिशा में आगे बढ़े।

वर्षा और समय-सीमा का प्रभाव

जल संरक्षण से जुड़ी किसी भी योजना की सफलता काफी हद तक वर्षा पर निर्भर करती है, स्थानीय स्तर पर यह जानकारी सामने आई है कि कई स्थानों पर गड्ढों का निर्माण वर्षा ऋतु के बाद किया गया, जिससे तत्काल प्रभाव का आकलन करना संभव नहीं हो सका, यदि पर्याप्त वर्षा नहीं होती, तो गड्ढों में जल संयोजन नहीं होगा और भूजल स्तर पर इसका प्रभाव भी सीमित रहेगा। इस कारण योजना के वास्तविक परिणाम सामने आने में समय लगना स्वाभाविक है।

पारंपरिक जल स्रोत बनाम नया मॉडल

योजना में पारंपरिक जल स्रोतों के पुनर्जीवन की बात जरूर कही गई है, लेकिन जमीनी स्तर पर इसका प्रभाव सीमित दिखाई देता है। आज के समय में कुओं का उपयोग कम हो रहा है और तालाबों का निर्माण भी सीमित स्तर पर हो रहा है, इसके विपरीत, खेतों में गड्ढे बनाने की गतिविधि अधिक दिखाई दी है, जिससे यह सवाल उठता है कि क्या पारंपरिक जल स्रोतों के संरक्षण पर पर्याप्त ध्यान दिया गया है।

पहल और प्रस्तुति के बीच संतुलन जरूरी

कोरिया जिले में जल संरक्षण को लेकर किए जा रहे प्रयास निश्चित रूप से महत्वपूर्ण हैं और इनका उद्देश्य भी दीर्घकालीन जल सुरक्षा से जुड़ा है, लेकिन वर्तमान स्थिति यह संकेत देती है कि जमीनी क्रियान्वयन, आंकड़ों की पारदर्शिता और वास्तविक प्रभाव इन सभी पहलुओं पर स्पष्टता आवश्यक है, यदि जल संरक्षण के प्रयासों को वास्तव में प्रभावी बनाना है, तो पारंपरिक जल स्रोतों का संरक्षण, रूफ वाटर हार्वेस्टिंग की अनिवार्यता और भूजल दोहन पर नियंत्रण जैसे उपायों को प्राथमिकता देनी होगी।

उपलब्धि, प्रयोग या अधूरी कहानी?

छत्तीसगढ़ में जल संरक्षण को लेकर किए जा रहे प्रयास निश्चित रूप से महत्वपूर्ण हैं और मोर गांव, मोर पानी तथा आवा पानी झोंकी जैसी पहलें इस दिशा में सकारात्मक कदम मानी जा सकती हैं, लेकिन कोरिया जिले के मॉडल को लेकर जो सवाल उठ रहे हैं, वे यह संकेत देते हैं कि किसी भी योजना की सफलता केवल प्रस्तुतीकरण से नहीं, बल्कि जमीनी प्रभाव और पारदर्शिता से तय होती है, यदि यह मॉडल वास्तव में प्रभावी है, तो इसके परिणाम समय के साथ स्पष्ट रूप से सामने आएंगे और यह अन्य क्षेत्रों के लिए भी उदाहरण बन सकता है, लेकिन यदि इसमें कमियां हैं, तो उन्हें स्वीकार कर सुधार करना भी उतना ही आवश्यक है।

समानता और अंतर: दो योजनाओं के बीच तुलना

मोर गांव, मोर पानी और आवा पानी झोंकी दोनों योजनाओं का मूल उद्देश्य जल संरक्षण है, लेकिन इनके क्रियान्वयन के स्तर और दृष्टिकोण में अंतर दिखाई देता है, राज्य स्तरीय अभियान मोर गांव, मोर पानी जहां व्यापक जनजागरूकता और सामुदायिक भागीदारी पर आधारित है, वहीं आवा पानी झोंकी खेत आधारित मॉडल के रूप में सामने आती है, जिसमें कृषि और जल संरक्षण को जोड़ने का प्रयास किया गया है, फिर भी, दोनों योजनाओं में सोखता गड्ढों के निर्माण और वर्षा जल को जमीन में समाहित करने की अवधारणा समान है, जिससे यह सवाल उठता है कि क्या यह वास्तव में नई योजना है या पहले से चल रही पहल का ही स्थानीय रूपांतरण।

डिस्कलेमर

यह समाचार उपलब्ध आधिकारिक जानकारी, स्थानीय स्रोतों, क्षेत्रीय चर्चाओं एवं विभिन्न पक्षों से प्राप्त इनपुट के आधार पर तैयार किया गया है, इसमें शामिल कुछ बिंदु स्थानीय अनुभवों और दावों पर आधारित हैं, जिनकी स्वतंत्र आधिकारिक पुष्टि सभी स्तरों पर नहीं हुई है, समाचार का उद्देश्य विषय के सभी पहलुओं को संतुलित और तथ्यात्मक रूप में प्रस्तुत करना है, संबंधित विभाग या प्रशासन की आधिकारिक प्रतिक्रिया प्राप्त होने पर जानकारी को अद्यतन किया जाएगा।

Koriya District is with Panchayat and Rural Development...
2h · Korea · 📍

राष्ट्रीय फलक पर कोरिया- 'मन की बात' में 5 प्रतिशत जल संरक्षण मॉडल की सराहना

जनभागीदारी से बढ़ती तस्वीर, भूजल स्तर में ऐतिहासिक वृद्धि।
देश के प्रधानमंत्री द्वारा 'मन की बात' कार्यक्रम में कोरिया जिले के अभिनव जल संरक्षण मॉडल का उल्लेख किए जाने के बाद यह जिला राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा का विषय बन गया है।

किसानों और ग्रामीण समुदाय की सक्रिय भागीदारी से विकसित '5 प्रतिशत मॉडल' ने न केवल जल संकट का समाधान प्रस्तुत किया है, बल्कि सतत विकास की दिशा में एक मजबूत उदाहरण भी स्थापित किया है।

@chhattisgarhcmo @dpr.chhattisgarh
#KoreaDistrict #Chhattishgarh

DPR Chhattisgarh is with Koriya District.
41m · 📍

छत्तीसगढ़ के कोरिया जिले में 'आवा पानी झोंकी' अभियान जल संरक्षण को अग्रेसरी मिलात बन रहा है। 1200 से अधिक किसानों के सहयोग से 2000 से ज्यादा सोखता गड्ढे और रिचार्ज तालाब बनाए गए, वहीं सामूहिक प्रयासों से 440 से अधिक पुराने तालाब पुनर्जीवित किए गए।

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 'मन की बात' कार्यक्रम में कोरिया जिले के इस जनभागीदारी आधारित जल संरक्षण मॉडल की विशेष सराहना की, जो छत्तीसगढ़ के लिए गर्व का विषय है। कोरिया का यह प्रयास अब पूरे देश के लिए प्रेरणा बन रहा है।

कोरिया जिले के जल संरक्षण मॉडल
की माननीय प्रधानमंत्री जी ने सराहना

370 नई एम्बुलेंस से मजबूत हुई स्वास्थ्य सेवा, 108 अब और तेज व हाई-टेक छत्तीसगढ़ में स्वास्थ्य क्रांति: 370 एम्बुलेंस के साथ 108 सेवा का विस्तार

अब 15 मिनट में पहुंचेगी एम्बुलेंस : 370 नई गाड़ियों से बदली 108 सेवा की तस्वीर

- नवजात के लिए 'चलता-फिरता ICU: 370 एम्बुलेंस के साथ नई स्वास्थ्य सुविधा शुरू
- 2019 से 2026 तक बड़ा बदलाव: 108 सेवा बनी तेज, सस्ती और हाई-टेक
- अब और तेज 108 सेवा, एम्बुलेंस नेटवर्क हुआ मजबूत, स्वास्थ्य सेवा को मिली रफ्तार



रायपुर, 31 मार्च 2026। छत्तीसगढ़ में आपातकालीन स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने 370 नई एम्बुलेंस को हरी झंडी दिखाकर प्रदेश के सभी जिलों के लिए रवाना किया, इस पहल के साथ ही 108 एम्बुलेंस सेवा को नए स्वरूप में पूरे राज्य में लागू कर दिया गया है, जिससे आपातकालीन परिस्थितियों में नागरिकों को त्वरित और गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा सहायता उपलब्ध कराई जा सकेगी, इस नई व्यवस्था के तहत 300 बेसिक लाइफ सपोर्ट और 70 एडवांस्ड लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस को सेवा में शामिल किया गया है, इसके साथ ही पहली बार राज्य में 5 नियोनेटल एडवांस्ड लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस की शुरुआत की गई है, जो नवजात शिशुओं के लिए अत्याधुनिक जीवनरक्षक सुविधा के रूप में काम करेगी, छत्तीसगढ़ में 108 एम्बुलेंस सेवा का यह विस्तार केवल संख्या बढ़ाने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह तकनीक, गुणवत्ता और पहुंच के स्तर पर एक व्यापक सुधार है, नियोनेटल एम्बुलेंस जैसी नई सुविधाएं और समयबद्ध सेवा का लक्ष्य इस पहल को और प्रभावी बनाते हैं। यह कदम प्रदेश में आपातकालीन स्वास्थ्य सेवाओं को नई दिशा देने वाला साबित हो सकता है और आम नागरिकों के लिए एक मजबूत जीवनरक्षक तंत्र के रूप में स्थापित होगा।



समयबद्ध सेवा का लक्ष्य : शहर में 15 मिनट... गांव में 30 मिनट...

इस पहल के साथ सरकार ने एम्बुलेंस सेवा की समयबद्धता को प्राथमिकता दी है, मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने स्पष्ट किया कि शहरी क्षेत्रों में 15 मिनट और ग्रामीण क्षेत्रों में 30 मिनट के भीतर एम्बुलेंस पहुंचाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है, स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने भी कहा कि यह लक्ष्य सुनिश्चित करेगा कि मरीजों को 'गोल्डन ऑवर' के भीतर उपचार मिल सके, जिससे गंभीर स्थितियों में जीवन बचाने की संभावना बढ़ेगी।

शुरुआत है, यह सेवा विशेष रूप से नवजात शिशुओं के लिए तैयार की गई है, इन एम्बुलेंसों में इन्क्यूबेटर, वेंटिलेटर, डिफ्रिजरेटर, सिरिज पंप, ऑक्सीजन सपोर्ट सहित सभी जरूरी उपकरण उपलब्ध हैं। साथ ही प्रशिक्षित तकनीशियन, इंफंटी और पायलट की 24x7 उपलब्धता सुनिश्चित की गई है, यह एम्बुलेंस नवजात शिशुओं को गंभीर स्थिति में सुरक्षित रूप से उच्च स्तरीय अस्पतालों तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी और राज्य में नवजात मृत्यु दर को कम करने की दिशा में

एक बड़ा कदम साबित हो सकती है। अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस बीएलएस और एडवांस्ड लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस- नई एम्बुलेंसों को आधुनिक चिकित्सा उपकरणों से लैस किया गया है, जिससे मरीजों को मौके पर ही प्राथमिक और उन्नत उपचार मिल सके, इनमें बीपी मॉनिटर, पल्स ऑक्सीमीटर, ईसीजी मॉनिटर, लूकोमीटर, नेब्युलाइजर, ऑक्सीजन सपोर्ट जैसे उपकरण शामिल हैं, गंभीर मरीजों के लिए पोर्टेबल वेंटिलेटर, डिफ्रिजरेटर और अन्य उन्नत उपकरण भी उपलब्ध कराए गए हैं, इससे



मरीज को अस्पताल पहुंचने से पहले ही आवश्यक उपचार मिलना संभव हो सकेगा।

तकनीकी सुधार: रियल टाइम मॉनिटरिंग और तेज प्रतिक्रिया

08 एम्बुलेंस सेवा को तकनीकी रूप से भी मजबूत किया गया है, लोकेशन वेड सर्विस के माध्यम से एम्बुलेंस की वास्तविक समय में ट्रैकिंग की जा सकेगी, मोबाइल डेटा टर्मिनल के उपयोग से सूचना मिलते ही एम्बुलेंस तुरंत मरीज तक पहुंच सकेगी, साथ ही, विशेष मॉनिटरिंग सिस्टम के जरिए सेवा में किसी भी प्रकार की देरी या कमी पर तत्काल कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।

2019 से 2026: सेवा में बड़ा बदलाव

प्रदेश में 108 एम्बुलेंस सेवा में पिछले कुछ वर्षों में उल्लेखनीय सुधार हुआ है, जहां वर्ष 2019 में यह सेवा सीमित दायरे में थी और सालभर में लगभग 3.28 लाख लोगों तक ही पहुंच पाती थी, वहीं अब वर्ष 2026 में यह संख्या बढ़कर 4.38 लाख से अधिक हो गई है, प्रति ट्रिप लागत भी घटकर 2293 से 1894 हो गई है, जबकि एम्बुलेंस की कार्यक्षमता बढ़कर प्रतिदिन 3 ट्रिप से 4 ट्रिप हो गई है, इसके साथ ही एम्बुलेंस की दैनिक दूरी क्षमता 120 किलोमीटर से बढ़कर 160 किलोमीटर हो गई है, नई एम्बुलेंस BS-VI और AIS-125 जैसे आधुनिक सुरक्षा मानकों से लैस हैं, जिससे मरीजों की सुरक्षा और सेवा की गुणवत्ता दोनों में सुधार हुआ है।

जनता को सीधा लाभ

इस नई व्यवस्था का सीधा लाभ आम नागरिकों को मिलेगा। अब हर वर्ष लगभग 1.10 लाख अतिरिक्त लोगों को 108 सेवा का लाभ मिल सकेगा, कम लागत में बेहतर सुविधाएं उपलब्ध होने से न केवल सरकारी खर्च में कमी आएगी, बल्कि आम जनता को अधिक प्रभावी स्वास्थ्य सेवाएं मिलेंगी, शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में समयबद्ध सेवा उपलब्ध होने से आपातकालीन स्थितियों में जीवन बचाने की संभावना भी बढ़ेगी।

मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री के विचार

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा कि राज्य में स्वास्थ्य सेवाएं लगातार मजबूत हो रही हैं और लोगों का विश्वास सरकारी अस्पतालों पर बढ़ रहा है, उन्होंने कहा कि यह नई एम्बुलेंस सेवा संकट के समय सरकार की संवेदनशीलता और तत्परता को दर्शाती है, स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने इस पहल को ऐतिहासिक बताते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ अब स्वास्थ्य सेवाओं के क्षेत्र में देश के अग्रणी राज्यों में शामिल हो रहा है, उन्होंने यह भी आश्वासन दिया कि सेवा में किसी भी प्रकार की कमी मिलने पर तत्काल कार्रवाई की जाएगी।

अमित जोगी को जमानत मिली... जग्गी हत्याकांड की अंतिम सुनवाई अप्रैल में

रायपुर, 31 मार्च 2026। जोगी काँग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अमित जोगी की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। जग्गी हत्याकांड मामले में अदालत ने उन्हें जमानत दी है, लेकिन उनके भविष्य को लेकर हालात अभी भी गंभीर हैं। निचली अदालत के न्यायाधीश पंकज कुमार सिन्हा की अदालत में अमित जोगी ने 50-50 हजार रूपय के बैंड और जमानत के पट्टे पेश किए, जिसके बाद उन्हें जमानत मिल गई। जग्गी हत्याकांड की गहन जांच के बाद मामले में अमित जोगी को आरोपी करार दिया गया था। निचली अदालत से जमानत मिलने के बावजूद उनका भविष्य पूरी तरह सुरक्षित नहीं है। इस मामले की अंतिम सुनवाई बुधवार को हाईकोर्ट में रखा गई है, और हाईकोर्ट के फैसले पर ही अमित



जोगी की आगे की राजनीतिक और कानूनी स्थिति तय होगी। जग्गी हत्याकांड राज्य में एक संवेदनशील और हाइप्रोफाइल मामला रहा है। इस मामले में अमित जोगी के ऊपर लगे आरोपों के गंभीर परिणाम हो सकते हैं। यदि हाईकोर्ट में उन्हें दोषी पाया गया, तो उन्हें जेल भी जाना पड़ सकता है। राजनीतिक हलकों में भी इस मामले को लेकर चर्चा तेज हो गई है और पार्टी नेतृत्व को भविष्य की रणनीति पर

काम करने के लिए मजबूर किया गया है। अमित जोगी ने निचली अदालत में जमानत लेते समय अपने पक्ष की दलीलें पेश कीं और अदालत ने उन्हें जमानत देने का फैसला किया। अब हाईकोर्ट की सुनवाई में सभी सबूत और गवाहों की दलीलों के आधार पर अंतिम निर्णय लिया जाएगा। राजनीतिक विशेषज्ञों का कहना है कि अगर हाईकोर्ट में दोष सिद्ध होता है, तो न केवल अमित जोगी की राजनीतिक छवि प्रभावित होगी बल्कि उनके नेतृत्व वाली पार्टी को भी असर पड़ेगा। इसके साथ ही राजनीतिक प्रतिद्वंद्वियों के लिए भी यह एक बड़ा मौका माना जा रहा है। अमित जोगी की जमानत मिलने के बावजूद पुलिस और न्यायिक अधिकारियों की नजरें इस पर बनी हुई हैं।

छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में 9 लाख के इनामी 5 नक्सलियों ने किया आत्मसमर्पण

दंतेवाड़ा, 31 मार्च 2026। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा जिले के पुलिस लाइन कारली में आज मंगलवार को 5 लाख की इनामी महिला नक्सली सोम कड़ती सहित पांच नक्सलियों ने आत्मसमर्पण कर दिया है। इन सभी आत्मसमर्पित नक्सलियों पर कुल 9 लाख रुपये का इनाम घोषित था। बस्तर आईजी सुंदरराज पी.सी.आर.पी.एफ.डीआईजी राकेश दंतेवाड़ा कलेक्टर देवेश कुमार धुव एवं दंतेवाड़ा एसपी गौरव राय के समक्ष आत्मसमर्पण के बाद उनकी निशानदेही पर सुरक्षाबलों ने नक्सलियों के विभिन्न ठिकानों पर छिपाकर रखी गयी ईंसास रायफल, एसएलआर एवं बीजीएल सहित कुल 40 हथियार भी बरामद किए। केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित नक्सली खात्मे की समय सीमा के अंतिम दिन आत्मसमर्पण करने वाले नक्सलियों में 5



लाख की इनामी भैरमाड एरिया कमेटी सदस्य सोम कड़ती बीजापुर जिला अंतर्गत थाना मिरतुर के चेरली निवासी, एक लाख की इनामी भैरमाड एरिया कमेटी पार्टी सदस्य लखमा पोयाम, निवासी बेचापाल

थाना मिरतुर, एक लाख की इनामी भैरमाड एरिया कमेटी पार्टी सदस्य सतिता पोडियम निवासी हिंम, थाना जंगला, एक लाख की इनामी जोगी कलमू निवासी नेंडा थाना बासागुडा, एक लाख की इनामी गंगलूर

एरिया कमेटी पार्टी सदस्य मोटी ओयाम निवासी पीडिडा, थाना गंगलूर शामिल हैं। पुलिस के अनुसार वर्ष 2024 से अब तक दंतेवाड़ा जिले में 607 नक्सली कैडर आत्मसमर्पण कर चुके हैं। वहीं, संयुक्त अभियानों में 92 नक्सलियों को गिरफ्तार किया गया है और 54 नक्सली मुठभेड़ों में मारे गए हैं।

बीजापुर में अब तक 19 करोड़ का डंडा मिला : जिले में 1 जनवरी 2024 से लेकर 31 मार्च 2026 तक कुल 1003 माओवादी कैडरों ने सरेंडर किया है। इसके पहले 5.37 करोड़ का डंडा मिला था, जिसमें 1.64 करोड़ का 1 किलो सोना और 3.73 करोड़ कैश था। इस प्रकार अब तक 19.43 करोड़ का डंडा मिला है। जिसमें 6.63 करोड़ कैश और 12.80 करोड़ का 8.20 किग्रा सोना शामिल है।

हाईकोर्ट ने रेप पीड़िता की गवाही को विरोधाभास माना, आरोपी बरी

बिलासपुर, 31 मार्च 2026। दुर्कर्म के एक मामले में आरोपी को सदेह का लाभ देते हुए हाईकोर्ट ने बरी कर दिया है। जस्टिस नरेंद्र कुमार व्यास की सिंगल बेंच ने यह फैसला सुनाया है। मामले राजनादगांव जिले के डोंगरगांव थाना क्षेत्र का है, जहां वर्ष 2003 में एक 20 वर्षीय युवती ने मूलचंद्र पर दुर्कर्म का आरोप लगाया था। पीड़िता के अनुसार, आरोपी ने रात में घर से खींचकर खेत में ले जाकर उसके साथ जबरदस्ती की थी और जान से मारने की धमकी भी दी थी। मामले में ट्रायल कोर्ट ने आरोपी को दोषी मानते हुए धारा 376 (दुर्कर्म) के तहत 7 साल की सजा और धारा 506-बी (धमकी) के तहत 6 माह की सजा सुनाई थी। आरोपी ने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 374 के तहत हाईकोर्ट में अपील की। हाईकोर्ट ने पूरे मामले की समीक्षा करते हुए पाया कि पीड़िता की गवाही स्टर्लिंग क्वालिटी की नहीं है। उसमें कई विरोधाभास और असंगतियां पाई गईं। सबसे महत्वपूर्ण तथ्य यह रहा कि घटना के 2-3 दिन बाद ही पीड़िता और आरोपी को साथ में देखा गया। ग्रामीणों की सलाह पर दोनों साथ रहने लगे और स्वयं पीड़िता ने माना कि यदि आरोपी उसे स्वीकार कर लेता तो एफआईआर दर्ज नहीं होती। इसके अलावा शरीर पर कोई चोट नहीं मिली, मेडिकल रिपोर्ट में जबरन संबंध के स्पष्ट संकेत नहीं मिले। एफएसएल रिपोर्ट भी नेगेटिव रही। घटना स्थल परों के बीच था जहां आवाज आसानी से सुनी जा सकती थी, बावजूद इसके किसी ने कोई शोर नहीं सुना।



प्रॉपर्टी टैक्स जमा करने की डेडलाइन 30 अप्रैल तक बढ़ी

करदाताओं को 30 दिन की राहत मिली, इसके बाद 17 प्रतिशत देना होगा एक्स्ट्रा चार्ज

रायपुर, 31 मार्च 2026। प्रॉपर्टी टैक्स जमा करने वाले लोगों को बड़ी राहत मिली है। नगरीय प्रशासन-विकास विभाग ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए संपत्ति कर भुगतान की अंतिम तारीख बढ़ाकर अब 30 अप्रैल 2026 कर दी है, जो पहले 31 मार्च थी। विभाग के आदेश के अनुसार सभी नगरीय निकायों को 30 दिनों का अतिरिक्त समय दिया गया है। राजस्व वसूली का लक्ष्य पूरा न होने और अन्य प्रशासनिक कारणों के चलते यह निर्णय लिया गया है। अब लोग 30 अप्रैल तक बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के संपत्ति कर जमा कर सकेंगे। इसके बाद भुगतान करने पर 17% सरचार्ज देना होगा।



9 करोड़ से ज्यादा की वसूली : डेडलाइन से पहले टैक्स जमा करने के लिए शहर में लोगों की भारी भीड़ देखने को मिली।

30 मार्च को सुबह 10 बजे से रात 9 बजे तक 8,768 संपत्ति करदाताओं ने नगर निगम से 9 करोड़ 58 लाख 61 हजार 442 रूपय जमा किए। नगर निगम के सभी 10 जनों के राजस्व कार्यालयों में दिनभर लोगों की भीड़ बनी रही।

सीलबंदी और नल कनेक्शन काटने की कार्रवाई : निगम ने साफ किया है कि बकाया नहीं चुकाने वालों पर सख्ती जारी रहेगी। ऐसे में दुकानों और व्यवसायिक परिसरों को सील किया जा रहा है। घरों में नल कनेक्शन काटने की कार्रवाई भी जारी है। यह कार्रवाई सभी जनों में लगातार चल रही है।

महासमुंद में 4.61 करोड़ का गांजा और नशीली-दवा पकड़ाई

महासमुंद, 31 मार्च 2026। छत्तीसगढ़ के महासमुंद जिले में पुलिस ने 'ऑपरेशन निश्चय' के तहत बड़ी कामयाबी हासिल की है। सोमवार को महज 10 घंटे के अंदर 4 थाना इलाके से 6 क्विंटल 85 किलो गांजा और 700 नशीली टैबलेट

बरामद किया है। जिसकी कीमत 4 करोड़ 61 लाख रूपय है। 13 तस्करों को भी गिरफ्तार किया गया है। यह कार्रवाई बसना, कोमाखान, सिंघोड़ा और महासमुंद थाना क्षेत्रों में की गई है। गिरफ्तार आरोपियों में 6 छत्तीसगढ़ और

7 ओडिशा, मध्यप्रदेश और उत्तरप्रदेश के रहने वाले हैं। यह आरोपी ड्राई फ्रूट से भरे ट्रक, घरेलू सामान, पैकर्स एंड मूवर्स की आड़ तस्करी कर रहे थे। नशे का सामान ओडिशा से यूपी-एमपी और राजस्थान ले जाया जा रहा था।

भू-माफियाओं पर बड़े एक्शन की तैयारी में निगम : अवैध प्लानिंग वाली जमीन पर कार्रवाई के साथ अधिग्रहण भी करेगा रायपुर निगम

रायपुर, 31 मार्च 2026। राजधानी में अवैध प्लानिंग करने वालों पर अब और सख्त कार्रवाई की तैयारी है। नगर निगम ऐसे मामलों में जमीन अधिग्रहण तक का कदम उठा सकता है। नए नियमों के तहत भू-माफियाओं पर शिकंजा कसने की योजना बनाई जा रही है। इसे लेकर जल्द ही आधिकारिक आदेश जारी हो



सकता है। जानकारी के मुताबिक, अवैध प्लानिंग और जमीन कब्जे के मामलों में एफआईआर दर्ज करने का अधिकार जिला प्रशासन के पास रहेगा। इससे कार्रवाई और तेज होने की संभावना है। प्रशासनिक स्तर पर ऐसे मामलों की पहचान कर सीधे कड़ी कार्रवाई करने की रणनीति बनाई जा रही है। निगम लगातार चला रहा